दैनिक

महाराष्ट्र समाचार

संपादक :अकबर खान

राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र

वर्ष:12 अंक:352 मुंबई, शनिवार, 11 अक्टूबर-2025 | E-mail:dailymaharashtrasamachar@gmail.com | मूल्य 3.00 रूपया | पृष्ठ - 06 | RNI.No.MAHHIN/2013/53656

आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस

जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन

चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार करेंगे नेतृत्व

पांच आईपीएस और सीपीएस अधिकारियों को टीम में शामिल किया गया है।

एजेंसी

चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार के सुसाइड मामले में विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। टीम का नेतृत्व चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार करेंगे। इनके अलावा पांच आईपीएस और सीपीएस अधिकारियों को टीम में शामिल किया गया है। एसआईटी में शामिल अन्य सदस्यों में चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप सिंह, एसपी सिटी केएम प्रियंका, डीएसपी (ट्रैफिक) चरणजीत सिंह विर्क, एसडीपीओ (साउथ) गुरजीत कौर और एसएचओ (पश्चिम) जयवीर सिंह राणा शामिल हैं। चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सागर प्रीत ने शुक्रवार को एसआईटी गठन के संबंध में आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया, 'एफआईआर संख्या 156/2025, धारा 108/3(5) बीएनएस और 3(1)(आर) एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 2013 के तहत पुलिस स्टेशन सेक्टर-11

(पश्चिम), चंडीगढ़ में आरोपों की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए आईजीपी, चंडीगढ़ की देखरेख में मामले की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का तत्काल प्रभाव से गठन किया जाता है।' आदेश के अनुसार, एसआईटी मामले में सभी पहलुओं की समयबद्ध तरीके से जांच करेगी, जिसमें साक्ष्य जुटाना, गवाहों से पूछताछ, विशेषज्ञों की राय और कानूनी सलाह जैसे विषय शामिल हैं। जांच पूरी होने पर एसआईटी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी। आदेश में यह भी बताया गया है कि एसआईटी जरूरत के अनुसार अन्य अधिकारियों और विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकती है।2001 बैच के आईपीएस अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे।

चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अधिकारी ने 9 पन्नों का एक 'सुसाइड नोट' छोड़ा, जिसमें 15 सेवारत और पूर्व अधिकारियों के नाम हैं।चंडीगढ़ पुलिस ने उनके 'सुसाइड नोट' में नामजद लोगों के खिलाफ सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की।

फिलहाल, इस मामले पर राजनीति जारी है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, 'अगर उन्हें न्याय नहीं मिला, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा सरकार के तहत किसे न्याय मिलेगा। एक अधिकारी, जिसने बार-बार न्याय मांगा, लेकिन उसे इनकार कर दिया गया।' शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सांसद मालविंदर सिंह कंग चंडीगढ़ में परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा, 'यह मौत अपने आप में कई सवाल खड़े करती है।'

राष्ट्रपति मुर्मु ने किए प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन

गांधीनगर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव का दर्शन पूजन किया और महादेव के चरणों में शीश झुकाकर माथा टेका। राष्ट्रपति ने भगवान सोमनाथ दादा से देश के नागरिकों के जनकल्याण और सुख-समृद्धि के लिए भावपूर्वक प्रार्थना की। उन्होंने भक्ति, भव्यता और दिव्यता के प्रतीक प्रथम ज्योतिर्लिंग के समक्ष गंगाजल अर्पित किया और दिव्य मंत्रोच्चार के बीच सोमेश्वर महापूजा कर धन्यता का

अनुभव किया। इसके पूर्व सोमनाथ मंदिर परिसर पहुंचने पर राष्ट्रपति का पर्यटन मंत्री मूलुभाई बेरा, सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव पी.के. लहेरी, ट्रस्टी जे.डी. परमार तथा ट्रस्ट के सचिव योगेंद्र देसाई ने स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति के साथ उनकी बेटी इतिश्री मुर्मु और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

भारत के कर सुधार निर्णायक चरण में

परदर्शी सिस्टम तैयार करने पर फोकस - नीति आयोग

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत के कर सुधार एक निर्णायक चरण में है और सरलीकरण, आधुनिकीकरण और कर प्रशासन में विश्वास के एकीकरण पर फोकस किया जा रहा है। यह जानकारी शुक्रवार को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम की ओर दी गई। उन्होंने कहा, 'जैसे-जैसे भारत प्रवर्तन-संचालित अनुपालन से विश्वास-आधारित शासन की ओर बढ़ रहा है, फोकस आनुपातिक, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रवर्तन सिस्टम पर केंद्रित होना चाहिए जो करदाताओं को सशक्त बनाते हुए राजकोषीय अखंडता की रक्षा करें।' नीति आयोग ने शुक्रवार को नीति टैक्स पॉलिसी वर्किंग पेपर सीरीज-II के तहत दूसरा वर्किंग पेपर जारी किया, जिसका शीर्षक 'भारत के कर परिवर्तन की ओर- गैर-अपराधीकरण और विश्वास-आधारित शासन' था। इस

वर्किंग-पेपर में आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत आपराधिक प्रावधानों का व्यापक मूल्यांकन किया गया है और उनकी आवश्यकता, आनुपातिकता और सरकार के व्यापक सुधार एजेंडे के साथ संरेखण का मूल्यांकन किया गया है। साथ ही, इसमें दंड को तर्कसंगत बनाने, छोटे और प्रक्रियागत गैर-अनुपालनों को अपराधमुक्त करने और न्यायिक विवेकाधिकार को सुदृढ़ करने के लिए सिद्धांत-आधारित ढांचे का प्रस्ताव किया गया है। नीति आयोग के वर्किंग-पेपर में कहा गया कि 2025 अधिनियम में कई पुराने अपराधों को खत्म कर दिया गया है, लेकिन 13 प्रावधानों में 35 कार्यों और गलती को आपराधिक श्रेणी में रखा गया है, जिनमें से अधिकांश में अनिवार्य कारावास का प्रावधान है। वर्किंग-पेपर में एक सुनियोजित गैर-अपराधीकरण रोडमैप की सिफारिश की गई है, जिसमें मामूली प्रक्रियागत चूक के लिए कारावास को हटाना, धोखाधड़ी या जानबूझकर कर चोरी से जुड़े मामलों तक ही आपराधिक दंड को सीमित करना और सिविल और प्रशासनिक सजा की भूमिका को बढ़ाना शामिल है। सुब्रह्मण्यम के अनुसार, ऐसे सुधारों से मुकदमेबाजी कम होगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के अनुरूप एक निष्पक्ष और पूर्वानुमानित कर व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।

सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका

पूर्व सांसद समेत कई नेता आरजेडी में शामिल

एजेंसी

पटना। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर चल रहे असमंजस के बीच, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल-यूनाइटेड (जेडीयू) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और एक मौजूदा सांसद के बेटे ने शुक्रवार को पटना में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का दामन थाम लिया। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में औपचारिक रूप से राजद का दामन थाम लिया। उनके साथ जहानाबाद से जदयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और बांका से जदयू सांसद गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश ने भी राजद का दामन थाम लिया। राहुल शर्मा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के पुत्र हैं और भूमिहार समुदाय से आते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ??है कि उनके शामिल होने से कई भूमिहार बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में राजद की पकड़ मजबूत हो सकती है, जिन्हें लंबे समय से जेडीयू का गढ़ माना जाता है। पटना स्थित राजद कार्यालय में आयोजित समारोह में अब्दुल बारी सिद्दीकी, जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव और बीमा भारती सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनकी सरकार को साढ़े तीन लोग नियंत्रित कर रहे हैं जो उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। वह दोबारा मुख्यमंत्री

नहीं बनेंगे। भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ देगी। महाराष्ट्र और झारखंड में ऑपरेशन लोटस के दौरान, उन्होंने 2022 में बिहार में भी जेडीयू को तोड़ने की यही कोशिश की थी। डर के मारे नीतीश कुमार मेरे पास आए और अपनी पार्टी बचाने के लिए मदद मांगी। हमने उनका समर्थन किया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने हमें फिर से धोखा दिया।

मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 24 अक्टूबर तक बढ़ी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने 24 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। वे तब तक जेल में ही रहेंगे। ईडी की ओर से मामले की जांच के लिए और समय की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में 18 जुलाई को भिलाई निवास स्थान से गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। आरोप है कि यह पैसा नकद में ठेकेदारों को भुगतान फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से उपयोग किया गया।

विदेश मंत्रालय ने 'स्पेशल क्लीनिंग कैंपेन 5.0' शुरू किया

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत'स्पेशल क्लीनिंग कैंपेन 5.0' शुरू किया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि यह अभियान 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। विदेश मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 4 से 31 अक्टूबर 2025 तक 'स्पेशल क्लीनिंग कैंपेन 5.0' शुरू किया गया है, जो स्वच्छता ही सेवा के तहत एक विशेष सफाई अभियान है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यालयों में स्वच्छ और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करना है। अभियान के दौरान मंत्रालय कार्यालयों में सफाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, कचरे के सही निपटान और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित निपटान और कार्य पेंडेंसी कम करने पर भी जोर रहेगा। इससे पहले, मंत्रालय ने 0स्वच्छता ही सेवा

31 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

2025' अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मंत्रालय के सभी कार्यालयों, विदेश मिशनों, पोस्टों और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में चलाया गया। इस दौरान 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 'स्वच्छ भारत दिवस' भी मनाया गया। विदेश मंत्रालय ने 'स्वच्छता ही सेवा 2025' के पांच मुख्य क्षेत्रों पर फोकस किया, जिसमें स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों का परिवर्तन, स्वच्छ सार्वजनिक स्थान, सफाईमित्र सुरक्षा शिविर, क्लीन ग्रीन उत्सव और जागरूकता अभियान शामिल रहे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस पहल का नेतृत्व किया और 25 सितंबर को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में -एक दिन, एक घंटा, एक साथ' श्रमदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत मंत्रालय ने पहले ही स्वास्थ्य शिविर, 25 से अधिक सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, 276 स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों की सफाई, स्वच्छता रन, साइक्लोथॉन, पेंटिंग व निबंध प्रतियोगिताए।

गरीबों का दीपावली से पहले घर का सपना साकार

सीएम योगी ने गोरखपुर में 160 परिवारों को सौंपी लैट की चाबी

एजेंसी

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले गोरखपुर में गरीबों को अनमोल उपहार सौंपा। पाम पैराडाइज, देवरिया बाईपास स्थित हाई-राइज बिल्डिंग में 160 परिवारों को ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैट्स की चाबियां भेंट कीं। इनमें 80 फ्लैट्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और 80 निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए हैं। साथ ही, गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 118 करोड़ रुपए की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम ने पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हर परिवार की एक तमन्ना होती है कि उसका अपना एक घर हो, सर ढकने को छत मिले। आज 160 परिवारों को यह दीपावली का शुभ उपहार मिल रहा है। कार्तिक मास के शुभ

मुहूर्त में यह उपलब्धि और भी खास है। उन्होंने कहा कि एक परिवार में औसतन 5-6 सदस्य होने पर करीब 700-800 लोग सीधे लाभान्वित हो रहे हैं।

यह किसी भी व्यक्ति के लिए केवल आवास ही नहीं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण घटना होती है। सीएम योगी ने कहा कि आवास वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ। जीडीए की हाउसिंग स्कीम में 40 विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता दी गई। शेष 120 परिवारों का चयन लॉटरी से हुआ। 9,000 से अधिक आवेदनों में से ये सौभाग्यशाली हैं। विकास प्राधिकरण को चाहिए कि बाकी जरूरतमंदों के लिए आवास प्रक्रिया तेज करे। ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स 35 वर्ग मीटर के हैं, जिनकी बाजार कीमत 13-15 लाख रुपये है, लेकिन सब्सिडी से मात्र 5.40 लाख रुपये में उपलब्ध हैं। एलआईजी फ्लैट्स 41 वर्ग मीटर के हैं, बाजार मूल्य 19-20 लाख के मुकाबले 10.80 लाख रुपये में। उन्होंने कहा कि जब सरकार और जनप्रतिनिधि ईमानदार होंगे तो गरीबों को अपना घर मिलने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकेशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस आवास के पास रामगढ़ ताल, जू और खोराबार के बेहतरीन स्थान हैं। यहीं पर कुछ दूरी पर सांसद रवि किशन का आवास भी है। हाई-राइज बिल्डिंग में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरणों को चाहिए कि हाई-राइज़ बिल्डिंग के रखरखाव के लिए आवासीय समितियां गठित हों, जिससे लिफ्ट और अन्य व्यवस्थाओं का नियमित मेंटेनेंस हो सके। उन्होंने पूर्व योजनाओं गोरख एंक्लेव, रप्ती नगर और पत्रकारपुरम का भी उल्लेख किया। हर तबके-गरीब, स्ट्रीट वेंडर, श्रमिक, पत्रकार, अधिवक्ता, चिकित्सक, शिक्षक और व्यापारियों के लिए भी समय-समय पर विशेष योजनाएं लाई जाएंगी। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के 11 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर 4 करोड़ गरीबों को फ्री आवास उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 60 लाख से अधिक गरीबों को आवास मिल चुके हैं। अच्छी नियत से अच्छे कार्य होते हैं। जनता अच्छी सरकार चुनती है, तो विकास गरीब तक पहुंचता है। सीएम योगी ने कहा कि खोराबार स्कीम जल्द आगे बढ़ेगी।

भारत और ब्रिटेन ने रक्षा सहयोग को और घनिष्ठ करने के तरीकों पर की चर्चा

मुंबई। भारत और ब्रिटेन ने मुंबई में शुक्रवार को रक्षा सहयोग को और घनिष्ठ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों के बीच यह चर्चा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री (हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मंत्री) वर्नोन कोकर के साथ द्विपक्षीय बैठक में हुई। यह बैठक ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (सीएसजी) की भारत यात्रा के दौरान आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मौजूदा रक्षा सहयोग की समीक्षा की और भारत तथा ब्रिटेन के बीच सहयोग को और घनिष्ठ करने के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा राज्य मंत्री सेठ ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि प्रिंस ऑफ वेल्स के नेतृत्व में ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने भारत के पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण-25 के समुद्री चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया। सीएसजी वर्तमान में मुंबई और गोवा में बंदरगाह चरण की गतिविधियों में लगा हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की परिचालन बातचीत परिचालन दर्शन की आपसी समझ को बढ़ाती है और दोनों नौ सेनाओं के बीच अंतर-संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले उपकरणों के निर्माण और स्वदेशी प्रणालियों के विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं पर चर्चा की।

मप्र के कफ सिरप मामले में कंपनी मालिक रंगनाथन को परासिया कोर्ट में किया पेश

10 दिन की मिली रिमांड

एजेंसी

भोपाल। मध्य प्रदेश में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 23 मासूम बच्चों की मौत के मामले में तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक गोविंदन रंगनाथन को एसआईटी ने चेन्नई से गिरफ्तार कर शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच छिंदवाड़ा जिले के परासिया की कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने पूछताछ के लिए उसकी रिमांड की मांग की। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जस्टिस शैलेंद्र उइके की कोर्ट ने रंगनाथन को 10 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। इस दौरान कोर्ट परिसर में आरोपित रंगनाथन पर हमले की कोशिश की गई। वहां मौजूद लोगों ने मारो और फांसी दो के नारे लगाए। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस मामले की जांच के लिए मप्र सरकार द्वारा गठित विशेष

टीम (एसआईटी) ने बुधवार की रात सिरप बनाने की कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल के मालिक गोविंदन रंगनाथन को बुधवार की रात चेन्नई से गिरफ्तार किया था और वहां स्थानीय अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड की मांग की। गुरुवार की रात चेन्नई से उसे लेकर रवाना हुई टीम नागपुर होते हुए शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे छिंदवाड़ा पहुंची। इसके बाद उसे छिंदवाड़ा से परासिया ले जाया गया, जहां सुबह 11 बजे से रंगनाथन को परासिया थाने में अभिरक्षा में रखा गया था। एसआईटी शाम को रंगनाथन को लेकर परासिया कोर्ट पहुंची। कोर्ट परिसर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। मामले को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था।

लोक सभा अध्यक्ष ने बारबाडोस की नेशनल असेंबलीका दौरा किया

एजेंसी

ब्रिजटाउन (बारबाडोस)। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के अवसर पर लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने बारबाडोस की नेशनल असेम्बली का दौरा किया। बारबाडोस के हाउस ऑफ असेम्बली के स्पीकर आर्थर होल्डर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों पक्षों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के आदान-प्रदान, वैश्विक मंचों पर साझेदारी और संसदीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। बिरला ने बारबाडोस संसद में भारत द्वारा 1966 में उपहार दी गई ऐतिहासिक अध्यक्षपीठ का अवलोकन किया, जो भारतीय सागौन की लकड़ी से निर्मित है और दोनों देशों की गहरी सांस्कृतिक साझेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत और बारबाडोस की लोकतांत्रिक परंपराएं दोनों देशों को करीब ला रही हैं और यह पीठ भारत-बारबाडोस मैत्री का जीवंत उदाहरण है। दोनों देशों ने शिक्षा, संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा और संसदीय सहयोग में नए अवसर तलाशने पर सहमति जताई। बारबाडोस में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात के दौरान बिरला ने कहा कि भारतीय समुदाय ने मेहनत, ईमानदारी और संस्कारों से विश्व में सम्मान पाया है। उन्होंने भारतीय त्योहारों को एकता का प्रतीक बताते हुए नई पीढ़ी से भारतीय भाषाएँ और संस्कृति सीखने का

आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत आज अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान और एआई जैसी तकनीकों में अग्रणी है और क्रिकेट दोनों देशों को जोड़ने वाला सांस्कृतिक सेतु है। सम्मेलन के दौरान बिरला ने ऑस्ट्रेलिया, जमैका और जाम्बिया के संसदीय नेताओं से द्विपक्षीय बैठकें कीं। उन्होंने संसदीय नवाचार, डिजिटल संसद और एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर विचार साझा किए।

बालिकाओं को उड़ान दें, समाज को नई दिशा दें

दिलीप कुमार पाठक

आज भी हमारे देश एवं दुनिया में बेटियों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के लिहाज से स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। भारत सहित पूरी दुनिया में लिंग भेद आज भी है, अन्यथा अमेरिका जो दुनिया को संस्कृति सिखाने का ठेकेदार बनता है, आज तक उनके देश में एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई। जब हम भारतीय परिपेक्ष्य में देखते हैं तो स्थिति और भी विकट है।

जब तक हमारे समाज में बेटियों के प्रति ज्यादतियां होती रहेंगी, तब तक हम कितना भी समृद्ध, उदारवादी विकसित समाज होने का ढोल पीट लें हमारी वास्तविकता कुछ और ही है। 2011 की जनगणनाः भारत में प्रति 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाएँ थीं, लिंगभेद की स्थिति इसी से समझी जा सकती है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है, जो शिक्षा में लिंग अंतर को दशार्ता है। उच्च शिक्षा में पुरुषों का अनुपात ज़्यादा है, और महिला शिक्षकों का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कम है। पुरुष शिक्षकों और उच्च शिक्षा में कुल नामांकित छात्रों की संख्या में महिलाओं की तुलना में अधिक है। कई सामाजिक कारक, जैसे कि कम उम्र में विवाह, बाल श्रम, और आर्थिक तंगी, लड़कियों की शिक्षा में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं और उनके स्कूल छोड़ने की दर को बढ़ाती हैं। आज भी हमारे देश एवं दुनिया में बेटियों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के लिहाज से स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। भारत सहित पूरी दुनिया में लिंग भेद आज भी है, अन्यथा अमेरिका जो दुनिया को संस्कृति सिखाने का ठेकेदार बनता है, आज तक उनके देश में एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई। जब हम भारतीय परिपेक्ष्य में देखते हैं तो स्थिति और भी विकट है। जब हमारे देश में हाथरस, मंदसौर, कोलकाता, उन्नाव, कठुआ, बुलन्दशहर, हैदराबाद आदि से रेप की दर्दनाक खबरें आती हैं और जहां से भी छोटी - छोटी बालिकाओं पर ज्यादतियों की खबरें आती हैं, तो पूरे समाज पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा एवं संस्कारों मे ये कैसी गिरावट है जहां छोटी - छोटी बालिकाएं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहीं हैं। लिंग भेद ऐसा कि अपनों के बीच भी बच्चियों को गैरों जैसा दोयम दर्जे का व्यवहार झेलना पड़ता है।

जब पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई ने बेटियों के शिक्षा का मुद्दा उठाया, तो कट्टरपंथी लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, ऐसे-ऐसे मुद्दे जब मेन स्ट्रीम में आते हैं, तब समाज की हकीकत सामने आ जाती है, दरअसल हमारे समाज में आज भी लड़कियों को लड़कों के बराबर न मानने वाले

लोगों की संख्या ज़्यादा है, हालांकि समाज के लिए सोचने वाले कुछ अग्रणी लोग एनजीओ के माध्यम से ही सही बालिकाओं के लिए कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं, परंतु ये काफी नहीं है। यही कारण है कि हर साल 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड यानी कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरूआत यूनाइटेड नेशन ने 2012 में की थी। इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य था लड़कियों के विकास के लिए अवसरों को बढ़ाना और लड़कियों की दुनियाभर में कम होती संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना, जिससे कि लिंग असमानता को खत्म किया जा सके। लिंग असमानता भारत सहित पूरी दुनिया की सच्चाई है।

इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह भी है कि समाज में जागरूकता लाकर लड़कियों को वे समान अधिकार दिलाए जा सकें, जो कि लड़कों को दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस को बढ़ावा देने के लिए इस दिन अलग-अलग देशों में कई तरह के आयोजन भी किए जाते हैं जिसके अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा, पोषण, उनके कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल के प्रति उन्हें और समाजजनों को जागरूक किया जाता है। लड़कियों को सुरक्षा मुहैया कराना, उनके प्रति भेदभाव व हिंसा खत्म करना। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना भी इस दिन को मनाने के कारणों में शामिल है। 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर, 2011 को प्रस्ताव 66/170 के माध्यम से घोषित किया गया था। इसे पहली बार 11 अक्टूबर, 2012 को मनाया गया था। यह वार्षिक दिवस 1995 के बीजिंग घोषणापत्र और कार्य योजना से जुड़ा है, जिसने पहली बार दुनिया भर में बालिकाओं के विशिष्ट अधिकारों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला था।

प्लान इंटरनेशनल ने इस पहल का नेतृत्व किया, जिसमें कनाडा सरकार सहित कई देशों का मजबूत समर्थन मिला। यह कार्यक्रम बालिकाओं के सशक्तीकरण, मानवाधिकारों और उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी भागीदारी के हित में, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भेदभाव और हिंसा जैसी बाधाओं पर दुनिया का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। इस दिन दुनिया भर में बालिकाओं के लिए एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता है।

आज 11 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम हैः ह्वद गर्ल आई एम, द चेंज आई लीडः गर्ल्स ऑन द फ्रंटलाइन्स ऑफ क्राइसिसह्व इस थीम का मुख्य फोकस उन परिस्थितियों पर है जिनका सामना बालिकाओं को करना पड़ता है, और उनकी दृढ़ता, नेतृत्व तथा मजबूत आवाजों पर, जो मानवीय, सामाजिक और पर्यावरणीय संकटों के खिलाफ खड़ी होती हैं। चूँकि संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और असमानताएँ बालिकाओं के खिलाफ असमान रूप से भारी पड़ती हैं, इसलिए यह विषय परिवारों, समुदायों और समाजों में परिवर्तनकारी भूमिकाएँ निभाने में उनके साहस को दशार्ता है। यह बालिकाओं को परिस्थितियों के शिकार के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन के वाहक के रूप में पहचानने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। लड़कियों के अनुभवों और नेतृत्व पर प्रकाश डालते हुए, यह थीम शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण में निवेश का आह्वान करती है ताकि वे सक्रिय रूप से एक बेहतर और अधिक समावेशी दुनिया का निर्माण कर सकें। यह नारा दुनिया को याद दिलाता है कि हर बालिका में क्षमताएँ भरपूर होती हैं और यह समाज का दायित्व है कि वह उनमें से प्रत्येक को संकट की स्थिति में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करें'

(लेखक पत्रकार हैं)

संपादकीय

विकास की नींव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन की उत्पादक यात्रा पर हैं। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन सहित विश्व नेताओं से द्वीपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन में शांति स्थापित करने के सभी प्रयासों का स्वागत करता है और यूक्रेन संघर्ष को यथा शीघ्र समाप्त करना मानवता का आह्वान है। यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष रचनात्मक तरीके से आगे बढेंगे। पुतिन ने कहा कि रूस और भारत ने दशकों से विशेष मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हैं, जो भविष्य के विकास की नींव हैं। उन्होंने इन संबंधों को दलगत राजनीति से ऊपर बताया और अधिकांश लोगों का समर्थन प्राप्त बताया। पुतिन ने रूस-यूक्रेन युद्ध को सुलझाने के लिए भारत और चीन के प्रयासों की सराहना की और यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों की भी आलोचना की। रूस हमेशा से भारत का मुखर समर्थक रहा है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थाई सदस्यता मिलने का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ड़ोनाल्ड़ ट्रंप के रूसी तेल और हथियार खरीदने पर भारत को दंड़ित करने के लिए 50प्र. टैरिफ लगाया है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। भारत और रूस, दोनों के बीच लगभग पंद्रह साल पहले शुरू हुई रणनीतिक साझेदारी के आधार पर द्विपक्षीय संबंध विकसित हो रहे हैं। इस मुलाकात को ट्रंप को सीधा चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका का आरोप है कि भारत पुतिन की युद्ध मशीनरी को वित्त-पोषित कर रहा है और रूसी ऊर्जा की बिक्री से भारी मुनाफा भी कमा रहा है जबकि भारत साफ कर चुका है कि रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख कर की गई है। चीन के बाद भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। देश के ऊर्जा आयात मास्को की हिस्सेदारी 40प्र. है। बेशक, भारत अपने दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों का बचाव करते हुए कहता रहा है कि हम अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देख सकते। इस बैठक को अमेरिका कैसे देखता है, से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कि व्यापार असंतुलन को सुधारने के प्रति सकारात्मक रणनीति बनाई जाए और व्यापार में विविधता लाने के प्रयास किए जाएं। भारत, चीन और रूस की इन उत्पादक बैठकों को देख कर अमेरिका की त्योरियां चढ़ने की अब कोई फिक्र करता नहीं नजर आ रहा।

चिंतन-मनन

सुखी रहने के लिए लें धर्म की शरण!

दुनिया का हर व्यक्ति केवल सुख ही चाहता है। दुख से सब दूर भागते हैं। यदि हमें सुखी रहना है तो सबसे पहले धर्म से जुड़ना होगा। किसी के मन को दुखाना भी पाप है। भागदौड़ भरी जिंदगी में आज हर व्यक्ति विवेक नहीं रख पाता है। इसलिए पाप बंध को बांधता चला जाता है और पाप बंधने के कारण सुखी नहीं हो पाता। इसलिए सुखी रहने के लिए धर्म की शरण में जाकर धर्म के मर्म को समझना होगा। धर्म की शुरूआत व्यक्ति को सबसे पहले अपने घर से ही करना चाहिए। यदि हम विवेकपूर्ण जीवन जिएंगे तो पाप से बच पाएंगे और जो पाप से बच पाएगा, वहीं सही मायनों में धर्म से भी जुड़ पाएगा। मयार्दाओं को भंग करना पाप की श्रेणी में आता है। इसी तरह किसी के मन को दुखाना भी पाप है। हमें अपने जीवन काल में सुख प्राप्ति के लिए जिनवाणी को आचरण में उतारना होगा, क्योंकि जिनवाणी अमृत रूप है। हमारा सौभाग्य है कि हमें जिनवाणी श्रवण का सुअवसर मिला है। जीवन में यदि सुख प्राप्त करना है तो जिनवाणी को आचरण में उतारना होगा।

धर्म आधारित जीवन जीते हुए ही मनुष्य वैराग्य की ओर अग्रसर हो सकता है। संपूर्ण जीवन लोभ, मोह, मद, मान और माया में ही व्यतीत हो जाता है और प्रभु आराधना का समय ही नहीं मिल पाता तथा व्यक्ति संसार से प्रस्थान भी कर जाता है। संसार में रहते हुए वैराग्य के प्रसंग जीवन में आते हैं। फिर भी विरक्ति नहीं होती। इसलिए निरंतर साधना व स्वाध्याय करते रहना चाहिए। सुखी और सफल जीवन के लिए भौतिक सुख नहीं, आध्यात्मिक सुख ज्यादा जरूरी है, जो वैराग्य से ही प्राप्त हो सकता है।

संसार के सभी जीव सुख चाहते हैं। सभी लोग सुख प्राप्त करने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सच्चा सुख कहां है, इसका हमें ध्यान नहीं है। जो जीवात्मा अरिहंत परमात्मा की वाणी को आत्मसात करती है, उसकी सभी प्रकार की आधि-व्याधि नष्ट हो जाती है। जिसने आत्मस्वरूप की पहचान कर ली है, वही धर्मध्यान में लीन होगा। हमारे आर्तध्यान और रौद्रध्यान से जीवन भटक जाता है। धर्मध्यान को अपनाकर व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में भी समभाव को धारण कर सकता है। आज धर्मध्यान की जगह धन का ध्यान ज्यादा किया जा रहा है। पैसा साधन जरूर है, पर वह साध्य नहीं है। विडंबना यह है कि आज व्यक्ति धन को ही साध्य मानने की भूल कर रहा है।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अवैध तस्करी रोकने में सक्रिय सामुदायिक सहायता की जरूरत हैं

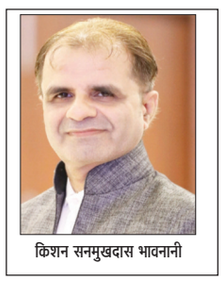

किशन सनमुखदास भावनानी

अंतरराष्ट्रीय स्तरपर मादक पदार्थों के सेवन और नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा उसकी अवैध तस्करी के मामलों से करीब-करीब हर देश पीड़ितहै और यह समस्या दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। खासकर मानवीय युवा पीढ़ी जिन्हें भविष्य की बागडोर संभालनीं है, यानें हमारी अगली पीढ़ी बनने वाले युवा और बच्चों की रुचि मादक पदार्थों में बढ़ती ही जा रही है।हम अपने आसपास भी देखते होंगे कि बच्चे भी सिगरेट, बीड़ी, बीयर पीने की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जो वैश्विक समस्या बनती जा रही है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यहां गुटखा पाबंदी होने के बावजूद स्कूलों के आसपास भी भारी मात्रा में तंबाकू युक्त गुटके मिलते रहते हैं जो बिना मिलीभगत के संभव नहीं है, नशा, एक ऐसी बीमारी है जो कि युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में लेकर उसे कई तरह से बीमार कर रही है।शराब, सिगरेट,तम्बौकू एवं ड्रग्सन जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन कर युवा वर्ग का एक बड़ा हि?स्सा नशे का शिकार हो रहा है। आज फुटपाथ और रेल्वे.प्ले टफार्म पर रहने वाले बच्चेंा भी नशे की चपेट में आ चुके हैं। लोग सोचते हैं कि वो बच्चेंक कैसे नशा कर सकते है जिनके पास खाने को भी पैसा नहीं होता। परंतु नशा करने के लिए सिर्फ मादक पदार्थों की ही जरुरत नहीं होती, बल्कि व्हाइटनर,नेल पॉलिश, पेट्रोल आदि की गंध, ब्रेड के साथ विक्स और झंडु बाम का सेवन करना, कुछ इस प्रकार के नशे भी किए जाते हैं, जो बेहद खतरनाक होते हैं।नशे की लत ने इंसान को उस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब व्यक्तिह मादक पदार्थों के सेवन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वह नशे के लिए जुर्म भी कर सकता है। नशे के मामले में महिलाएं भी पीछे नहीं है। महिलाओं द्वारा भी मादक पदार्थों का बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में तनाव, प्रेम संबंध, दांपत्य जीवन व तलाक आदि कारण, महिलाओं में नशे की बढ़ती लत के लिए जिम्मेदार है इसीलिए ही नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ हम इस आर्टिकल के माध्यम से,आओ नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अवैध तस्करी को रोकने सक्रिय भूमिका बढ़ाएं पर परिचर्चा करेंगें।

साथियों बात अगर हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की करें तो, ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) ने उल्लेख किया है, एक साथ, हम विश्व नशीली दवाओं की समस्या से निपट सकते हैं। मजबूत दृढ़ संकल्प और नशीली दवाओं से संबंधित ज्ञान साझा करके, हम सभी नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एकअंतरराष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।जब ड्रग्स का दुरुपयोग व्यापक रूप से समाज के अमीर और गरीब वर्ग के बीच फैल जाता है तो उस समय सबसे अधिक अनिवार्य है नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सामुदायिक सहायता की जरूरत की। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ युद्ध में प्रसिद्ध कहावत रोकथाम इलाज से बेहतर है, काफी प्रासंगिक है। ड्रग्स के दुरुपयोग और इससे जुड़ी अवैध तस्करी के खिलाफ जनजागृति बढ़ाना जरूरी है।

साथियों बात अगर हम मादक पदार्थों की करेंतो गुटखा तंबाकू तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां, मदिरा अफीम, कोकीन, भांग, चरस, गांजा , हशीश, एलएसडी आदि अन्य पदार्थ भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलन में है। युवा इनको प्रयोग विभिन्न कारण से कर बैठते हैं और चंगुल में फंस जाते हैं। इनके प्रयोग से दुष्प्रभाव परिवार से विच्छेदन, अपराध प्रवृति की वृद्धि शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं। कुछ समय के लिए मस्ती देनेवाले नशीले द्रव्यों के निरंतर सेवन से मनुष्य के तन-मन निष्क्रिय और शिथिल हो जाते हैं, दृष्टि कमजोर हो जाती है, पाचनशक्ति मंद पड़ जाती है तथा हृदय और फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। इससे स्वास्थ्य चौपट हो जाता है और मनुष्य असमय ही मृत्यु का द्वार खटखटाने लगता है। नशीली दवाओं की लत एक कट्टर दानव है जो हमारे समाज के विकास पर रोक लगा सकती है। कैंसर जैसी अनेक भयंकर बीमारियां हमेशा सक्रियता से होने का डर बना रहता है।

साथियों बात अगर हम भारत में नशा मुक्ति के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं, की करें तो भारत में नशा मुक्ति के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ताकि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को रोका जा सके।यहां कुछ प्रमुख सरकारी प्रयासों का विवरण दिया गया हैः(1)नशा मुक्त भारत अभियान-यह अभियान अगस्त 2020 में शुरू किया गया था,इसका उद्देश्य देशभर में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना, लोगों को सहायता देना और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना है।अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा चुका है, 3 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान और 8,000 से अधिक मास्टर वॉलंटियर्स इस अभियान में जुड़े हैं। (2) कानूनी और प्रशासनिक सख्ती-नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत सख्त कानून बनाए गएहैं2014 के बाद से ड्रग्स के मामलों में 152 पेर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, गिरफ्तारियों में 400 पेर्सेंट की वृद्धि हुई है और जब्त की गई ड्रग्स का मूल्य 30 गुना बढ़ा है। 2014 से अब तक 12 लाख किलोग्राम से अधिक ड्रग्स नष्ट की गई हैं। (3) इंटर-एजेंसी समन्वय और तकनीकी उपाय - नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर और जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है।सिम्स पोर्टल विकसित किया गया है, जिससे ड्रग्स से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग और डेटा ट्रैकिंग आसान हुई है।समुद्री मार्गों की निगरानी के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है। (4) जागरूकता और शिक्षा-स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। युवाओं और अभिभावकों के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और

काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाते हैं, ताकि वे नशे के दुष्परिणाम समझ सकें और समय रहते मदद ले सकें। (5) पुनर्वास और सहायता केंद्र- देशभर में सरकारी और गैर-सरकारी पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां नशा पीड़ितों को इलाज, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा मिलती है। (6) सीमा सुरक्षा और तस्करी पर नियंत्रण-भारत की सीमाओं पर सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत किया गया है, ताकि ड्रग्स की तस्करी को रोका जा सके।ड्रग्स की तस्करी के मामलों में वित्तीय जांच और संपत्ति जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई की जा रही है। (7) समुदाय और परिवार की भागीदारी-सरकार समुदाय और परिवारों को भी नशा मुक्ति अभियान में शामिल कर रही है, ताकि समाज का हर वर्ग इसमें भरपूर स्वेच्छा से सहयोग दे सके।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि,नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अवैध तस्करी रोकनें में सक्रिय सामुदायिक सहायता की जरूरत हैं, नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने समुदायिक सहायता की जरूरत है।मादक पदार्थों के प्रयोग से दुष्प्रभाव-परिवारों से विच्छेदन, आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि, शारीरिक व मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आती है।

बदलाव एवं विकास की राह ताकता बिहार चुनाव

पंकज चतुर्वेदी

इस बार की बरसात उत्तराखंड में भूस्खलन से तबाही की नई इबारत लिख गई और चेतावनी भी दर्ज कर गई कि राज्य में पहाड़ गिरने का खतरा अब पूरे साल, हर मौसम में बना हुआ है । इस साल के तीन महीने में 1000 से अधिक भूस्खलन दर्ज किए गए हैं, जिनमें 260 से अधिक लोगों की जान गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की हालिया लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में रूद्रप्रयाग जनपद भूस्खलन के लिहाज से देश का सबसे संवेदनशील जिला बन गया है। इसरो की लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया में 17 राज्यों के 147 जिलों का विश्लेषण किया गया है। उत्तराखंड के सभी 13 जिले इस सूची में शामिल हैं, जिसमें रूद्रप्रयाग पहले और टिहरी दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक उत्तराखंड में इस वर्ष मानसून में भूस्खलन और भूधंसाव के 25 से अधिक नए स्पॉट सामने आए हैं। पिछले दिनों डॉ मुरलीमनोहर जोशी, डॉ कर्ण सिंह, शेखर पाठक, के गोविंदाचार, रामचन्द्र गुहा सहित 57 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर अपने सितंबर-2022 के उस निर्णय को बदलने का अनुरोध किया है जिसमें चार धाम के लिए चौड़ी सड़क बनाने पर अदालत ने मंजूरी दी थी । इस बीच भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) की ताजा रिपोर्ट ने उत्तराखंड के पहाड़ों अपर रहने वालों की चिंताएं और बढ़ा दी है जिसमें बताया गया है कि राज्य का 22 फीसदी हिस्सा भूस्खलन को ले कर गंभीर, जबकि 32 प्रतिशत माध्यम और प्रतिशत निम्न खतरे में आ रहा हैं। इस मानसून में राज्य को भूस्खलन के चलते तीन हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। जी एस आई ने साफ खा हैं कि आल वेदर रोड, हायड्रो पावर प्रोजेक्ट और बेतहाशा निर्माण के चलते पहाड़ों पर खतरा और बढ़ गया हैं।

इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर 203 भूस्खलन जोन चिह्नित किए गए हैं। देहरादून- पिथौरागढ़ मार्ग पर एक-दो नहीं बल्कि 60 भूस्खलन जोन को चिह्नित किया गया। ऑलवेदर रोड पर गौचर के पास कमेड़ा भूस्खलन जोन का स्थायी समाधान बीते तीन साल में नहीं निकल पाया है। यहां पहाड़ी के बड़े हिस्से में हो रहे भूस्खलन से बदरीनाथ हाईवे को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कमेड़ा में हालात नहीं सुधर पाए कि अब बदरीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग के पास उमट्टा ने मुसीबत बढ़ा दी है। यहां बीते वर्ष पहाड़ी के हिस्से से मलबा आया था। गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे वल्णावत पर्वत की तलहटी में बसा है। यहाँ भूस्खलन का मतलब पूरे रिहायशी इलाके का खतरे की जद में आना है। वल्णावत पर्वत का पूरा क्षेत्र कई मायनों में बेहद संवेदनशील है। भूकंप के लिहाज से यह बेहद खतरनाक है । साल 1991 में यहां रिक्टर स्केल पर 6। 1 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। एक बात और, यहाँ घने चीड़ के जंगल हैं और अब इनमें गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं । वनों की कटाई, निर्माण के लिए पहाड़ों को तोड़ने के अलावा मिट्टी की पकड़ ढीली होने का यह भी बड़ा कारण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के डाटा के अनुसार 1988 से 2023 के बीच उत्तराखंड में भूस्खलन की 12,319 घटनाएं हुईं। सन 2018 में प्रदेश में भूस्खलन की 216 घटनाएं हुई थीं जबकि 2023 में यह संख्या पांच गुना बढ़कर 1100 पहुंच गई। 2022 की तुलना में भी 2023 में करीब साढ़े चार गुना की वृद्धि भूस्खलन की घटनाओं में देखी गई है। पिछले साल भूस्खलन की 2946 घटनाएं दर्ज की गई जिनमें 67 लोगों की मौत हुई थी ।

उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग और विश्व बैंक ने सन 2018 में एक अध्ययन करवाया था जिसके अनुसार छोटे से उत्तराखंड में 6300 से अधिक स्थान भूस्खलन जोन के रूप में चिन्हित किये गये। रिपोर्ट कहती है कि राज्य में चल रही हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं पहाड़ों को काट कर या जंगल उजाड़ कर ही बन रही हैं और इसी से भूस्खलन जोन की संख्या में इजाफा हो रहा है। दुनिया के सबसे युवा और जिंदा पहाड़ कहलाने वाले हिमालय के पर्यावरणीय छेड़छाड़ से उपजी सन 2013 की केदारनाथ त्रासदी को भुला कर उसकी हरियाली उजाड़ने की कई परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य के भविष्य के लिए खतरा बनी हुई हैं । उत्तराखंड में बन रही पक्की सड़कों के लिए 356 किलोमीटर के वन क्षेत्र में कथित रूप से 25 हजार पेड़ काट डाले गए। मामला एनजीटी में भी गया लेकिन तब तक पेड़ काटे जा चुके थे। यही नहीं सड़कों का संजाल पर्यावरणीय लिहाज से संवेदनशील उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी के से भी गुजर रहा है। उत्तराखंड के चार प्रमुख धामों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना में 15 बड़े पुल, 101 छोटे पुल, 3596 पुलिया, 12 बाइपास सड़कें

बनाने पर काम चल ही रहा है । ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलमार्ग परियोजना भी स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें ना सिर्फ बड़े पैमाने पर जंगल कटेंगे, वन्य जीवन प्रभावित होगा और पहाड़ों को काटकर सुरंगे और पुल निकाले जाएंगें।

हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र में भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ टकराव होता है और इसी से प्लेट बाउंड्री पर तनाव ऊर्जा संग्रहित हो जाती है जिससे क्रिस्टल छोटा हो जाता है और चट्टानों का विल्पण होता है। ये ऊर्जा भूकंपों के रूप में कमजोर जोनों एवं फाल्टों के जरिए सामने आती है। जब पहाड़ पर तोड़फोड़ या धमाके होते हैं, जब उसके प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड होती है तो दिल्ली तक भूकंप के खतरे तो बढ़ते ही हैं यमुना में कम पानी का संकट भी खड़ा होता है। देवभूमि, विकास में पर्यावरण संरक्षण, नैसर्गिक विकास और आस्था में सुख को त्याज्य करने की भावना विकसित करने के लिए आमंत्रित भी कर रही है और चेता भी रही हैं। खासकर जब इस साल दिसम्बर तक बरसात के लंबे खींचने की संभावना है, सरकार को अतिरिक्त सतर्क रहना होगा ।

दैनिक महाराष्ट्र समचार मलिक मुद्रक प्रकाशांन व संपादक अकबर खान प्लोट ने 302, वी पी वर्डे रोड ए ,आर औटो वोर्क्स बिहाइंड गेटी सिनेमा बांद्रा वैस्ट मुंबई -400050 महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर 9152073782. प्राचीता प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड- गला नः13 मकबा बिल्डिंग नियर एस ब्रिज एन एम जोशी मर्ग भैकल्ला वैस्ट मुंबई- 400027. किसी भी सुरत में न्याय क्षेत्र मुंबई होगा।

1.45 करोड़ की लूट मामले में टीआई सहित 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड

सिवनी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में सिवनी पुलिस पर 1.45 करोड़ की लूट के आरोप लगे हैं। मामले कार्रवाई करते हुए आईजी प्रमोद वर्मा ने बंडोल टीआई सहित 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, सीएसपी पूजा पांडे के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि कटनी से नागपुर के लिए एक कारोबारी अपनी गाड़ी में हवाला के 1.45 करोड़ लेकर जा रहा था। तभी पुलिस को इस बात की सूचना मिली, इसके बाद गाड़ी को सीलादेही के पास रोककर 1.45 करोड़ बरामद किए गए। आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई न करने का आश्वासन देकर व्यापारी को जाने देकर राशि का गबन किया। दूसरे दिन जब व्यापारी वापस पहुंचा और कोतवाली में पूरी घटना की शिकायत दी। तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। निलंबित पुलिसकर्मियों में बंडोल टीआई अर्पित भैरम, सीएसपी का रीडर रविंद्र उइके, ड्राइवर, दो गनर, सीएसपी कार्यालय में तैनात दो आरक्षक और बंडोल थाने का एक आरक्षक शामिल है। आईजी वर्मा ने बताया कि 1.45 करोड़ की बरामदगी के मामले में बंडोल टीआई सहित 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही सीएसपी पूजा पांडे के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है।

तमिलनाडु के प्रसिद्ध तिरुचेंदूर सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में कुल 5.28 करोड़ का चढ़ावा आया

थूथुकुडी (एजेंसी)। तमिलनाडु के प्रसिद्ध तिरुचेंदूर सुब्रमण्य स्वामी मंदिर को श्रद्धालुओं से भारी मात्रा में चढ़ावा मिला है। मंदिर प्रशासन के अनुसार, हाल ही में खुले हंडियों (दानपात्र) से कुल 5.28 करोड़ का चढ़ावा प्राप्त हुआ है। इसमें नकद राशि के साथ 1,905 ग्राम सोना और 72,255 ग्राम चांदी शामिल है। शुक्रवार को चढ़ावे की गिनती का कार्य शुरू हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस प्रक्रिया की निगरानी ठक्कर अरुलमुरुगन और जॉइंट कमिश्नर रामू कर रहे हैं। गिनती में शिवकाशी पथिनेन सिद्धार मठ पीडम टीम की मदद ली जा रही है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मंदिर प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। तिरुचेंदूर सुब्रमण्य स्वामी मंदिर भगवान मुरुगन के छह प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है। यहां हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से त्यौहरों और कार्तिगई दीपम के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त चढ़ावे का उपयोग मंदिर के रखरखाव, सामाजिक कल्याण और भक्तों की सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा। सोना और चांदी को धार्मिक परंपराओं के अनुसार संरक्षित किया जाएगा। इस भारी चढ़ावे ने एक बार फिर तिरुचेंदूर मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को उजागर किया है, जहां भक्त आस्था और श्रद्धा के साथ अपनी भेंट अर्पित करते हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 37 दिनों में फैसला, आरोपी को 20 साल की जेल और 50 हजार जुर्माना

भुवनेश्वर (एजेंसी)। भुवनेश्वर में विशेष न्यायाधीश प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) सह चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खुर्दा ने ऐतिहासिक और त्वरित फैसले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 37 दिनों के भीतर दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सुभंजन मोहंती ने दुष्कर्म और गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले में मामला दर्ज होने की तारीख से 37 दिनों के भीतर दोषसिद्धि का फैसला सुनाया। दोषी मुन्ना बेहरा को 20 साल के सश्रम कारावास (आरआई) और 50,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना ना देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को अदालत द्वारा पीड़िता को छह लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। विशेष लोक अभियोजक सुब्रत प्रियदर्शिनी ने भुवनेश्वर के अभियोजन उप निदेशक हेमंत कुमार स्वाई की सक्रिय निगरानी में मामले की सुनवाई की थी।

आतंकी जैश संगठन अब महिलाओं का कर रहा ब्रेनवॉश, तैयार कर रहा ब्रिगेड

-पढ़ी-लिखी और शहरी महिलाओं को आकर्षित करने दे रहा धार्मिक रंग

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसमें जैश का हेडक्वार्टर भी शामिल था। अब एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जैश के आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद अब महिलाओं का एक ब्रिगेड तैयार कर रहा है। 2024 के बाद से महिलाओं के बीच प्रभाव बढ़ाने के मकसद से जैश ने जमात अल-मुमिनात नाम की महिलाओं की ब्रिगेड तैयार की है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप का जिक्र एक सर्कुलर में किया गया है, जिसका इस्तेमाल महिला सदस्यों की भर्ती और उन्हें प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट में खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जमात अल-मुमिनात जैश-ए-मोहम्मद का महिला विंग है, जो साइकोलॉजिकल वारफेयर और ग्राउंड लेवल पर भर्ती के लिए काम कर रहा है। यह ग्रुप जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्यों में ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए सक्रिय है। इसका काम धर्म के नाम पर महिलाओं का ब्रेनवाश करना है। सूत्रों के मुताबिक जैश के सर्कुलर में मक्का और मदीना की तस्वीरें लगाई गई है ताकि संगठन की बातों को धार्मिक रंग दिया जा सके। वहीं इसके जरिए पढ़ी-लिखी और शहरी महिलाओं को आकर्षित करने के लिए भावनात्मक बातें भी लिखी गई हैं। जैश की तरह जमात अल-मुमिनात भी सेल-आधारित स्ट्रक्चर पर काम करती है। इसके अलग-अलग ग्रुप सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को भर्ती करने, चंदा जुटाने और संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। सर्कुलर के पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत भी मिले हैं।

आज़ाद मैदान मे आशा आंदोलन ये गेंद राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पाले मे?

आशा-समूह प्रवर्तक कर्मचारी कार्य समिति ने स्वास्थ्य मंत्री और आयुक्त के साथ विस्तृत चर्चा की; सरकार कई मांगों पर सकारात्मक रुख रखती है।

मुंबई/ अकबर खान

मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएँगे, रिचार्ज भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया जाएगा; भाऊबिज यात्रा पर कैबिनेट स्तर पर विचार; समूह प्रवर्तकों को संविदा कर्मचारी का दर्जा देने और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

मुंबई। आशा-समूह प्रवर्तक कर्मचारी कार्य समिति मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने मुंबई के आज़ाद मैदान मे विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से खराब हस्तक्षेप का आरोप लगाया।

महाराष्ट्र राज्य आशा-समूह प्रवर्तक कर्मचारी कार्य समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबितकर, स्वास्थ्य सेवा आयुक्त एवं निदेशक कादंबरी बलकावड़े, संयुक्त निदेशक (ए. तकनीकी) राजेंद्र भालेराव, राज्य समन्वयक स्वाति पाटिल के साथ विस्तृत चर्चा की। इस चर्चा में, कार्य समिति ने कहा कि सरकार कई लंबित मांगों पर सकारात्मक रुख रखती है। वही

स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबितकर, ने आशा और समूह प्रवर्तकों को भाऊबिज यात्रा के मुद्दे पर कैबिनेट स्तर पर चर्चा करने और निर्णय लेने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि समूह प्रवर्तकों को संविदा कर्मचारी का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजकर उसका अनुवर्तन किया जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य आयुक्त एवं निदेशक कादंबरी बलकवड़े, के सभाकक्ष में हुई बैठक में आशा महिलाओं को मोबाइल रिचार्ज भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने का निर्णय भी लिया गया और नए मोबाइल फोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने संबंधी पूर्व आदेश पर पुनर्विचार किया जाएगा। समूह प्रवर्तकों को एक ही रंग की वर्दी उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। यह भी स्पष्ट किया गया कि ऑनलाइन कार्य के संबंध में कोई बाध्यता नहीं है और यदि अन्य विभागों द्वारा आशाओं से कोई ऑनलाइन कार्य कराया जा रहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वे आयुक्त स्तर पर उस विभाग से पत्राचार करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि बकाया मानदेय का तुरंत भुगतान करने और लड़की बहिन योजना के अंतर्गत पंजीकरण का पारिश्रमिक दिलाने के लिए अनुवर्तन किया जाएगा। कार्य समिति को राहत मिली कि समूह प्रवर्तकों के लिए बायोमेट्रिक्स अनिवार्य नहीं किया जाएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर आशाओं की दैनिक उपस्थिति की ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

यह भी आश्वासन दिया गया कि सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव और आयुक्त के स्तर पर कार्य समिति के साथ जल्द ही एक व्यापक बैठक आयोजित की जाएगी। यह भी कहा गया कि अगस्त और सितंबर माह का मानदेय अगले तीन दिनों में राज्य सरकार द्वारा जमा कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में आशा और समूह प्रवर्तकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए जाएँगे।

इसके बाद, कार्य समिति ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और अजित पवार, व स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर, और संबंधित अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा जायेगा।

मुख्य माँगें हैं

पाँच माह (मई से सितंबर 2025) का बकाया केंद्रीय अंश का मानदेय तुरंत भुगतान किया जाए।

केंद्र और राज्य निधि से हर महीने की 5 तारीख तक नियमित मानदेय प्राप्त हो।

5G मोबाइल फोन, सिम कार्ड और असीमित डेटा पैक मिलने तक ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार जारी रखा जाए।

दिवाली से पहले 5,000 रुपये का भाईचारा उपहार मिलना चाहिए।

समूह प्रवर्तकों को संविदा कर्मचारियों की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए और न्यूनतम वेतन 35,000 रुपये लागू किया जाना चाहिए।

आशा कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए या उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह निर्वाह भत्ता दिया जाए।

बायोमेट्रिक उपस्थिति समाप्त की जाए।

स्वास्थ्य केंद्रों पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए आवास कक्षों की व्यवस्था की जाए।

पूर्ण वेतन सहित मातृत्व और बीमारी अवकाश लागू किया जाए।

कार्य करते समय मृत्यु होने पर, उत्तराधिकारियों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

इन मांगों की स्वीकृति के लिए 10 अक्टूबर, 2025 को सुबह 11 बजे आज़ाद मैदान, मुंबई में एक विशाल मार्च और तीव्र प्रदर्शन किया गया।

प्रतिनिधिमंडल में कॉमरेड शामिल थे। राजू देसले, भगवान देशमुख, नीलेश दातखिले, दत्ता देशमुख, वैशाली खंडारे, पुष्पा पाटिल, अरमैती ईरानी, ज्योति उराडे, चंद्रा कांबले, मधुकर कदम आदि। राज्य भर से बड़ी संख्या में आशा और समूह प्रवर्तकों ने आंदोलन में भाग लिया।

महाराष्ट्र उर्दू अकादमी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर फ़ोटोग्राफ़र /पत्रकार इम्तियाज़ शेख को उर्दू अकादमी द्वारा विशेष पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित

मुंबई / अकबर खान

मुंबई। फ़ोटोग्राफ़र और पत्रकार इम्तियाज़ शेख को महाराष्ट्र उर्दू अकादमी द्वारा विशेष पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह पुरस्कार उर्दू अकादमी की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार में 15,000 रुपये की नकद राशि भी शामिल है।

इम्तियाज़ शेख पिछले कई वर्षों से मुंबई उर्दू न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और उनकी फ़ोटोग्राफ़ी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। उर्दू पत्रकारिता में विजुअल रिपोर्टिंग के क्षेत्र में वे एक सम्मानित नाम बन गए हैं। यह पुरस्कार उनकी निरंतर कड़ी मेहनत और पत्रकारिता की भावना को देखते हुए दिया जा रहा है।

मुंबई पर हुए भीषण आतंकवादी हमलों की रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। इम्तियाज़ शेख को उनकी उत्कृष्ट पत्रकारिता सेवाओं के लिए अब तक विभिन्न संगठनों द्वारा सात बार सम्मानित किया जा चुका है। इनमें बॉम्बे प्रेस क्लब और मराठी पत्रकार सिंह जैसे मीडिया संगठन शामिल हैं, जिन्होंने इम्तियाज़ शेख की पत्रकारिता सेवाओं की सराहना की है और उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया है।

उल्लेखनीय है कि इम्तियाज़ शेख ने अपने दो दशक के पत्रकारिता सफर में विभिन्न समाचार पत्रों में एक फोटोग्राफर और पत्रकार के रूप में काम किया है। इनमें 2:00 PM, उर्दू टाइम्स, पीटीआई, मिड-डे, गेटी इमेजेज़, अनादोलु एजेंसी तुर्की, ग़हरत समाचार, सन टीवी, टाइम्स ऑफ़ इंडिया और मुंबई उर्दू न्यूज़ शामिल हैं।

महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एडवोकेट माणिक राव कोकाटे और उर्दू अकादमी के सीईओ एस. शोएब हाशमी ने इस अवसर पर इम्तियाज़ शेख को बधाई दी और उनकी पत्रकारिता सेवाओं को नमन किया।

इम्तियाज़ शेख के परिवार, दोस्तों और पत्रकार समुदाय ने उन्हें पत्रकारिता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के बाद खुशी जताई। इसके साथ ही, इम्तियाज़ शेख ने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी को उनकी उत्कृष्ट पत्रकारिता सेवाओं के लिए उन्हें चुनने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले दो दशकों से पत्रकारिता सेवाएं प्रदान कर रहा हूं और भविष्य में भी अपनी पत्रकारिता सेवाएं प्रदान करता रहूंगा। मैं अपने संगठन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की सेवा करने का अवसर दिया।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के अध्यक्ष राम कुमार पाल ने महामंडलेश्वर से की मुलाकात

मुंबई / अकबर खान

मुंबई। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भ भारत के अध्यक्ष राम कुमार पाल ने परमपूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी डॉ. उमाकान्तानंद सरस्वती जी महाराज के दरबार में दर्शन कर लिया आशीर्वाद।

महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा-अर्चना का कार्यक्रम विधि-विधान से संपन्न हुआ, उन्होंने कहा कि जहाँ उन्हें आत्मिक शांति मिलती है।

राम कुमार पाल में उत्साह का माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों ने स्वागत किया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई।

गोरेगांव मल्टीस्पेशलिटी पशु चिकित्सालय के पुनर्निर्माण को मंजूरी

- पालक मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार की अनुवर्ती सफलता
- मुंबई उपनगरों में पशु प्रेमियों के लिए राहत!

मुंबई / अकबर खान

मुंबई। गोरेगांव स्थित मुंबई पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में एक आधुनिक मल्टीस्पेशलिटी पशु चिकित्सालय के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया है। इस पहल के लिए 58.22 करोड़ रुपये के प्रारंभिक बजट को आज ही सरकार के कृषि एवं पशुपालन विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उपनगर पालक मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से सीधे संपर्क किया था। मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और आज इस पशु चिकित्सालय के पुनर्निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी। उपनगर पालक मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि उपनगरों में घरेलू और जंगली जानवरों के लिए उत्कृष्ट उपचार और सेवा सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

नए भवन में एक भूतल और तीन मंजिलें हैं और यह लगभग 10,210 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अस्पताल बड़े और छोटे, दोनों तरह के जानवरों के लिए अत्याधुनिक और बहु-विषयक सेवाएँ प्रदान करता है। यह सुविधा उपनगरों और मुंबई के विभिन्न हिस्सों से पशु उपचार के लिए आने वाले नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। इस परियोजना को वास्तुकारों द्वारा अनुमोदित किया गया है, यह सौर ऊर्जा प्रणालियों से निर्मित है और इसमें पर्यावरण-अनुकूल विशेषताएँ शामिल हैं।

सरकार का यह निर्णय पशु प्रेमियों, किसानों, निवासियों और मुंबई महानगरीय क्षेत्र के कई लोगों की लंबे समय से चली आ रही माँग को पूरा कर रहा है। नया बहु-विशिष्ट पशु चिकित्सालय पशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार लाएगा, और श्री आशीष शेलार ने इस महत्वाकांक्षी पहल को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लिया है।

मुंबई पुलिस का महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को अनुमति देने से इनकार

महामोर्चा आजाद मैदान में आएगा : रामदास अठावले

मुंबई / अकबर खान

मुंबई। बौद्ध नेताओं की सार्वजनिक घोषणा मुंबई, बिहार के बोधगया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए 14 अक्टूबर को मुंबई के आजाद मैदान में एक लाख बौद्धों का मार्च निकाला जाएगा। यह घोषणा आज सभी राजनीतिक दलों के बौद्ध नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इस बीच, हालांकि पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ मे संवाददाताओं से कहा कि यह बौद्ध समुदाय का कार्यक्रम है और इसे शांतिपूर्वक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस सांसद चंद्रकांत हंडोरे खा. इस अवसर पर वर्षा गायकवाड़, पीआरपी के प्रो. जोगेंद्र कवाडे, नानासाहेब इंदिसे, आरपीआई के राजेंद्र गवई, एनसीपी विधायक संजय बनसोडे, शिवसेना के राजू वाघमारे, भाजपा के भाई गिरकर, अविनाश महातेकर, गौतम सोनवणे, जयदीप कवाडे, यूआरपी के तनसे नानावरे, भीम आर्मी के नितिन मोरे, सुनील निर्भावने, मिलिंद सुर्वे, विलास रूपवते और अन्य नेता उपस्थित थे।?. इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने आगे कहा कि बोधगया में महाबोधि विहार पर हिंदुओं ने अतिक्रमण किया है। 1949 के अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। हालांकि, महाबोधि विहार का पूरा नियंत्रण बौद्धों को सौंपने के लिए यह मोर्चा निकाला गया है और पूरी अंबेडकर रिपब्लिकन जनता पंचशील ध्वज के नीचे एकजुट हो रही है। 0 प्रहर में महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपने के लिए संसद में चर्चा हुई। यह जानकारी कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने बोलते हुए दी। सांसद चंद्रकांत हंडोरे ने कहा कि बौद्ध नेता एक साथ आए हैं, इसलिए यह मार्च सफल होगा। मार्च का नेतृत्व प्रकाश अंबेडकर-आठवले को करना चाहिए। जब सभी बौद्ध नेता महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए एक साथ आए थे, इस समय प्रकाश अंबेडकर, आनंदराज अंबेडकर और भीमराव अंबेडकर अनुपस्थित थे। जब रामदास अठावले का ध्यान इस ओर दिलाया गया, तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर परिवार इस मार्च के विरोध में नहीं है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर को इस मार्च का नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन क्या अंबेडकर परिवार शायद नाखुश है क्योंकि मैं खुद इस मार्च का नेतृत्व कर रहा हूं? अठावले के जवाब देते ही सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े... तानसेन नानावरे को खड़ा होना पड़ा... महाबोधि महाविहार आंदोलन के लिए 14 अक्टूबर के मार्च की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बौद्ध नेताओं में भारी उत्साह था। देर से पहुँचे भाजपा नेता भाई गिरकर को जगह देने के लिए रिपब्लिकन नेता तानसेन नानावरे को अपनी कुर्सी से उठना पड़ा। रिपब्लिकन पार्टी के महाराष्ट्र महासचिव गौतम सोनवणे ने सभी बौद्ध नेताओं का स्वागत किया।

संक्षिप्त समाचार

चीनी राष्ट्रपति के सियासी दल में शामिल महिला से हुआ अमेरिकी राजनयिक को प्रेम, ट्रंप प्रशासन ने छीनी नौकरी

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मामला कुछ इस प्रकार से है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक अमेरिकी राजनयिक को केवल इस वजह से नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक चीनी महिला से प्रेम संबंध की बात छुपाई थी। बताया जा रहा है कि उस महिला के सीधे संबंध चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी राजनयिक को इस कारण से निकाला गया है। बता दें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में एक नियम लागू किया था, जिसके तहत चीन में तैनात किसी भी अमेरिकी सरकारी कर्मचारी, उनके परिवार या सुरक्षा क्लियरेंस वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को किसी भी चीनी नागरिक से प्रेम या यौन संबंध बनाने पर रोक लगा दी गई थी। मामले में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने बताया कि राजनयिक को इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने चीनी महिला से अपने रिश्ते को छिपाया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस मामले की समीक्षा की और फिर इस मामले में कार्रवाई की गई है। पिगॉट ने आगे कहा कि विदेश मंत्री रुबियो के नेतृत्व में हम राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे। हालांकि राजनयिक का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन वह और उसकी गर्लफ्रेंड एक गुप्त रूप से बनाए गए वीडियो में नजर आए थे जिसे मशहूर रूढ़िवादी पत्रकार जेम्स ओ'कीफ ने ऑनलाइन पोस्ट किया था।

रेबेका ग्रिनस्पैन संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए नामित

सैन होज़े, एजेंसी। कोस्टा रिका ने अपने लंबे समय से सक्रिय कूटनीतिज्ञ और पूर्व उपराष्ट्रपति रेबेका ग्रिनस्पैन को संयुक्त राष्ट्र का अगला महासचिव बनने के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया है। ग्रिनस्पैन वर्तमान में जेनेवा स्थित यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के महासचिव हैं और उन्हें यूक्रेन-रूस युद्ध के दौरान अनाज को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के संयुक्त राष्ट्र प्रयास में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। कोस्टा रिका के राष्ट्रपति रॉड्रिगो चावेस ने वीडियो संदेश में कहा कि ग्रिनस्पैन का अनुभव और विकास, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा क्षेत्रीय नेतृत्व में योगदान बहुपक्षवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। उनका नामांकन आने वाले हफ्तों में संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक रूप से दर्ज किया जाएगा।

कांगो में इबोला के नए मामले नहीं मिले : डब्ल्यूएचओ

किंशासा, एजेंसी। दक्षिणी कांगो में फैले इबोला वायरस पर अब नियंत्रण के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि 1 अक्तूबर के बाद से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। डब्ल्यूएचओके अनुसार, 5 अक्तूबर तक पिछले 10 दिनों में संक्रमण के कोई नए मामले दर्ज नहीं हुए, जिससे संकेत मिलता है कि प्रभावित इलाकों में संक्रमण की श्रृंखला अब टूट रही है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, अब तक कुल 64 मामले (53 की पुष्टि और 11 संदिग्ध) दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 43 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि बेहतर लॉजिस्टिक्स, हेलिकॉप्टर से मेडिकल सप्लाई, ग्राउंड डिलीवरी और तीन स्वास्थ्य केंद्रों के डी-कंटेमिनेशन जैसी कार्रवाइयों से संक्रमण पर काबू पाया जा सका है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है क्योंकि लगभग 2,000 संपर्कों पर नजर रखी जा रही है और एक भी छूटा हुआ मामला संक्रमण को फिर से फैला सकता है।

ह्यूस्टन में दो जगहों पर गोलीबारी, चार की मौत

ह्यूस्टन, एजेंसी। अमेरिका के टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन में बुधवार को हुई दो अलग-अलग गोलीबारी की घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें हमलावर भी शामिल है। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चलता है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि पहली वारदात दोपहर लगभग 1 बजे शुगर लैंड उपनगर में हुई, जहां एक व्यक्ति ने अपनी कार से दूसरी गाड़ी पर गोली चलाई। घायल चालक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह रोड रेज (सड़क विवाद) का मामला था या नहीं। करीब आधे घंटे बाद ह्यूस्टन शहर के एक मैकेनिक वर्कशॉप में दूसरी गोलीबारी की सूचना मिली। पुलिस अधिकारी लेरी क्रॉसन के अनुसार, हमलावर ने एक मैकेनिक और एक गवाह को गोली मारी। गवाह उस समय घटना का वीडियो बना रहा था। जांच में दोनों घटनाओं में शामिल वाहन और हमलावर के विवरण समान थे। कुछ समय बाद पुलिस ने हमलावर को उसकी गाड़ी में मृत पाया।

ट्रंप की कोशिशों को लग सकता है झटका, नोबेल मिलने के आसार कम; खुद को भी नहीं है भरोसा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि, जानकारों का कहना है कि इस साल ट्रंप की इच्छा पूरे होने के आसार कम हैं। खुद ट्रंप भी कह रहे हैं कि नोबेल कमेटी उनके बजाए किसी और को पुरस्कार देने की वजह खोज लेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान समेत 7 युद्ध रुकवाए हैं। एएफपी से बातचीत में स्वीडन के प्रोफेसर पीटर वालेनस्टीन ने कहा, नहीं, ट्रंप इस साल नहीं जीतेंगे। उन्होंने कहा, लेकिन शायद अगले साल? तब तक गाजा संकट समेत उनकी कई पहलों पर स्थिति साफ हो चुकी होगी।

कौन जीत सकता है पुरस्कार : खबर है कि इस साल 338 लोग और संगठन नॉमिनेशन प्रक्रिया में हैं, लेकिन यह सूची गुप्त रखी जाती है। नॉमिनेट करने वालों में सांसद, सरकारी अधिकारी, पूर्व विजेता और कमेटी के सदस्य शामिल होते हैं। साल 2024 में यह पुरस्कार जापान के एटम बम पीड़ितों से जुड़े निहोन हिदान्यको को मिला था। साफ नहीं है कि 2025 की रेस में कौन-कौन है। माना जा रहा है कि सुडान के इमरजेंसी रिस्पॉन्स रूम, रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलनी की विधवा यूलिया नवलनाया और चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने वाले ऑफिस फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स एंड ह्यूमन राइट्स का नाम दौड़ में शामिल हो सकता है। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, यूएनआरडब्ल्यूए के नाम पर मुहर लग सकती है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बार नोबेल कमेटी अपने चुनाव से सभी को चौंका सकती है। भारतीय समयानुसार शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजकर 30 मिनट पर पुरस्कार की घोषणा की जा सकती है।

तो इस बार कौन हो सकता है विजेता : जब ये बात लगभग-लगभग तय मानी जा रही है कि ट्रंप को इस बार नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने जा रहा है। तो ये सवाल भी लगातार सामने आ रहा है कि अगर ट्रंप नहीं तो कौन? ध्यान रहे कि नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे (भारतीय समयानुसार) ओस्लो में की जाएगी। ऐसे में इस पुरस्कार के लिए इस बार 338 व्यक्ति और संस्थाओं को नामांकित किया गया है। हालांकि, नामों की आधिकारिक सूची 50 वर्षों तक गोपनीय रखी जाती है। 2024 में यह पुरस्कार जापान के निहोन हिदानक्यो को मिला था, जो परमाणु हमलों के जीवित बचे लोगों का संगठन है। दूसरी ओर इस बार विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार विजेता के नाम का चयन थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। कारण है कि इस साल की स्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि दुनिया भर में संघर्ष चरम पर हैं। इस्राइल और ईरान की सीधी भिड़ंत, गाजा में संघर्ष, भारत-पाकिस्तान के बीच ड्रोन और मिसाइल हमले, थाईलैंड-कंबोडिया सीमा विवाद जैसी घटनाओं ने माहौल तनावपूर्ण बना दिया है। 2024 में रिकॉर्ड संख्या में राज्य-स्तरीय युद्ध भी हुए थे, जैसा कि स्वीडन की उप्साला यूनिवर्सिटी के डेटा से पता चलता है।

इस साल 338 नामांकनों में कौन हैं प्रमुख दावेदार : 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कई प्रभावशाली नाम चर्चा में हैं। सूडान की इमरजेंसी रिस्पॉन्स रूम्स, जो युद्ध प्रभावित इलाकों में लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, एक मजबूत दावेदार मानी जा रही है। वहीं रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की विधवा यूलिया नवलनाया भी इस सूची में शामिल हैं, जो अपने पति की विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ा रही हैं। इसके अलावा, ऑफिस फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन राइट्स , जो चुनाव निगरानी और लोकतंत्र की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, भी एक प्रमुख उम्मीदवार है। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं भी हो सकती हैं पुरस्कार की हकदार वहां कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नोबेल समिति इस बार वैश्विक व्यवस्था के समर्थन में कोई संदेश देना चाहेगी, खासकर उन नेताओं के खिलाफ जो इसे चुनौती दे रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे में संभावित विजेताओं की सूची में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, यूएनएचसीआर (शरणार्थी मामलों की एजेंसी), यूएनआरडब्ल्यूए (फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी) का भी नाम शामिल है।

हालांकि ठीक इसके इतर कुछ का मानना है कि वैश्विक न्याय या प्रेस स्वतंत्रता को लेकर काम करने वाली संस्थाओं को भी इस बार सम्मान मिल सकता है, जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स और रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स का नाम शामिल है।

अंतरिम सरकार और सहयोगियों के बीच सियासी खींचतान; एनसीपी ने सलाहकार की निष्ठा पर खड़े किये सवाल

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश की मुहम्मद युनुस-नेतृत्व वाली अस्थायी सरकार और उसके प्रमुख सहयोगी, छात्र-नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के बीच सियासी खींचतान बढ़ती जा रही है। एनसीपी ने आरोप लगाया कि सरकार के सलाहकार बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच सुरक्षित निकास की तलाश कर रहे हैं। हालांकि, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मामलों की सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा मैं किसी भी तरह का निकास नहीं ढूंढ रही। मैं अपना शेष जीवन बांग्लादेश में बिताऊंगी। उन्होंने एनसीपी नेताओं से स्पष्ट जवाब की मांग की कि उन्होंने ऐसा आरोप क्यों लगाया। एनसीपी ने ही हसीना को सत्ता से हटाया था एनसीपी ने फरवरी में युनुस के आशीर्वाद से राजनीतिक रूप में अपनी पहचान बनाई। यह पार्टी छात्रों के विरोध आंदोलन स्रष्ठ की एक बड़ी शाखा है, जिसने पिछले साल की 'जुलाई क्रांति' में हिंसक सड़कों पर प्रदर्शन किया और 5 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को सत्ता से हटाया। सुरक्षित निकास पर हंगामा बढ़ा युनुस ने अस्थायी सरकार में छात्रों के तीन प्रतिनिधियों को सलाहकार परिषद में शामिल किया। हालांकि, बाद में युनुस ने एनसीपी का नेतृत्व संभालने के लिए इस्तीफा दे दिया, जबकि दो अन्य सदस्य सलाहकार बने रहे। एनसीपी के अनुसार, कई सलाहकार राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। एनसीपी के समन्वयक सरजिस आलम ने कहा कुछ सलाहकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सोच रहे हैं। सुरक्षित निकास का विकल्प केवल मृत्यु में है।

लोग उनका पीछा करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी इस बीच, बांग्लादेश की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और 29 अन्य के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। हालांकि, अस्थायी सरकार ने कहा कि वह सभी राजनीतिक दलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखती है और एनसीपी नेताओं के आरोपों की व्याख्या उनकी जिम्मेदारी है। बांग्लादेश में आगामी फरवरी में राष्ट्रीय चुनावों से पहले यह सियासी उठापटक देश में राजनीतिक अस्थिरता और तनाव की नई लकीर खींच रही है।

बेबी पाउडर से मौत, जॉनसन एंड जॉनसन को देना होगा 8,500 करोड़ का मुआवजा

कैलिफोर्निया, एजेंसी। अमेरिका में लॉस एंजिलिस की अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन को मेसोथेलियोमा कैंसर से मरने वाली एक महिला के परिवार को 8,500 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने कंपनी को महिला की मौत के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए यह जुर्माना लगाया। परिजनों ने दावा किया था कि महिला ने जिंदगी भर कंपनी के बेबी पाउडर इस्तेमाल किया। इसके चलते उन्हें कैंसर हुआ। जूरी ने फैसले में माना, जॉनसन एंड जॉनसन ही महिला मे मूर को हुए कैंसर के लिए जिम्मेदार है। यह एस्बेस्टस से जुड़ा है। जूरी ने मुआवजे के रूप में करीब 140 करोड़ रुपये और सजा के तौर पर 8,360 करोड़ रुपये परिवार को देने का आदेश दिया। मूर का 2021 में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। परिवार का आरोप था, कंपनी ने पाउडर में कैंसर के जोखिमों को स्पष्ट न कर धोखा दिया। परिवार की वकील जेसिका डीन ने कहा, हमें अदालत में पक्ष साबित करने में पांच साल लगे। मूर ने इस बेबी पाउडर के साथ शावर-टू-शॉवर का पाउडर भी करीब 80 साल तक उपयोग किया था। कंपनी ने 2012 में शावर-टू-शॉवर को वैलेंट फार्मा को 15 करोड़ डॉलर में बेच दिया था। जॉनसन एंड जॉनसन के वैश्विक कानूनी मामले संभालने वाले एरिक हास ने कहा कि हम इस गंभीर फैसले के खिलाफ तुरंत अपील करेंगे। यह फैसला ज्यादातर बेबी पाउडर मामलों से बिल्कुल विरोधाभासी है, जिनमें कंपनी ने जीत हासिल की है।

कंपनी पर हजारों मुकदमे 3 अरब डॉलर किए खर्च : कंपनी ने बेबी पाउडर में मौजूद एस्बेस्टस से मुकदमों से निपटने में 3 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए हैं। फिर भी कंपनी पर 70,000 से ज्यादा ऐसे मुकदमे लंबित हैं, जिनमें आरोप है कि इसके कारण मेसोथेलियोमा व डिम्बग्रंथि के कैंसर हुए हैं।कंपनी ने इस पाउडर को 2023 में दुनियाभर के बाजारों से वापस ले लिया था। उसने इनसे निपटने के लिए दिवालियापन अदालतों का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन उसकी कोशिश तीन बार असफल हो गई है।

ड्रग माफियाओं पर बेरोकटोक कार्रवाई करते रहेंगे ट्रंप! राष्ट्रपति की शक्तियों पर निगरानी का प्रस्ताव खारिज

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सीनेट में बुधवार को एक बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिला। रिपब्लिकन सांसदों ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए लाया गया था। यह प्रस्ताव ट्रंप को मादक पदार्थों के कार्टेल पर आगे की सैन्य कार्रवाई से पहले कांग्रेस से अनुमति लेने के लिए बाध्य करता। इस प्रस्ताव के पक्ष में 48 और विरोध में 51 वोट पड़े। वोटिंग में ज्यादातर रिपब्लिकन सांसदों ने विरोध किया। सिर्फ दो रिपब्लिकन ने समर्थन किया जबकि एक डेमोक्रेटिक सांसद ने विरोध में वोट डाला।

ट्रंप की युद्ध अधिकार की घोषणा : ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कैरिबियाई क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जहाजों को निशाना बनाकर सैन्य हमले किए। व्हाइट हाउस का कहना है कि चार जहाज नष्ट किए गए, 21 लोगों की मौत हुई और अमेरिका में पहुंचने वाली बड़ी मात्रा में ड्रग्स को रोका गया। प्रशासन का दावा है कि ड्रग तस्कर सशस्त्र दुश्मन हैं और उन पर युद्ध की तरह कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इस पर कांग्रेस में असहमति गहराती जा रही है।

क्या है वॉर पावर्स रिजॉल्यूशन?

वॉर पावर्स रिजॉल्यूशन ऑफ 1973, एक ऐतिहासिक कानून है, जो वियतनाम युद्ध के बाद बनाया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस की अनुमति के युद्ध शुरू करने से रोकना है। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को किसी भी सैन्य अभियान के लिए कांग्रेस से स्पष्ट मंजूरी लेनी होती है।

विपक्ष का तर्क- कांग्रेस की शक्ति छीनी जा रही है : डेमोक्रेटिक सांसदों ने कहा कि ट्रंप बिना कांग्रेस की अनुमति के सैन्य हमले नहीं कर सकते। उनके अनुसार यह अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय कानून दोनों का उल्लंघन है। टिम केन और एडम शिफ ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस वोटिंग ने भले ही कानून पास न कराया हो, लेकिन यह एक मजबूत राजनीतिक संदेश गया है कि हर कोई राष्ट्रपति की असीमित शक्ति से सहमत नहीं। रैंड पॉल, जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं लेकिन लंबे समय से युद्ध अधिकारों पर कांग्रेस की भूमिका को मजबूत करने के पक्षधर हैं, उन्होंने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस को कार्यपालिका को जज, ज्यूरी और जल्लाद बनने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। रिपब्लिकन का रुख- देश की सुरक्षा पहले दूसरी ओर, रिपब्लिकन नेताओं ने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। जिम रिस्क, जो सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के प्रमुख हैं, ने कहा कि ड्रग्स अमेरिकी नागरिकों को मारने का हथियार बन चुके हैं। उन्होंने कहा, जो जहाज नष्ट किए गए, उनमें जो जहरीला माल था वो अब समुद्र की गहराइयों में है। मार्को रूबियो ने रिपब्लिकन सीनेटरों को समझाने के लिए लंच मीटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कई कार्टेल अब कैरेबियाई देशों के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर चुके हैं और वे सरकारों की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये संगठन अमेरिकी सड़कों पर हिंसा और अपराध फैला रहे हैं। राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे। सीनेट सशस्त्र सेवा समिति को पिछले हफ्ते ट्रंप प्रशासन ने एक गोपनीय ब्रीफिंग दी थी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए कई रक्षा समझौते, राजनाथ सिंह और रिचर्ड मार्ल्स रहे मौजूद

कैनबरा, एजेंसी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस की उपस्थिति में प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिवसीय दौरे के तहत बीते दिन सिडनी पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया और भारत की रक्षा साझेदारी लगातार हो रही मजबूत इस समझौते के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ऑस्ट्रेलिया और भारत की रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है - जो विश्वास, साझा हितों और शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया-भारत रक्षा मंत्रियों की पहली वार्ता के लिए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। समझौते पर ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री का बयान वहीं इस समझौते के बाद ऑस्ट्रेलियाई उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने कहा, मुझे लगता है कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो गहरा विश्वास और रणनीतिक तालमेल देख रहे हैं, वह अब दोनों रक्षा बलों के बीच कहीं अधिक गहन परिचालन स्तर की सहभागिता में व्यक्त हो रहा है। हमारे परिचालन कमांडों के बीच स्टाफ वार्ता के संदर्भ में हमने जो समझौता किया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है... हम इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं। कैनबरा में रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर मंथन इसके अहम रक्षा समझौते के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने कार्यक्रमों के तहत ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा पहुंचे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील और संयुक्त अभियान प्रमुख वाइस एडमिरल जस्टिन जोन्स ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से मिले राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा स्थित संसद भवन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स तथा दोनों पक्षों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के साथ कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में बैठक की। बाद में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भी बैठक में शामिल हुए। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से राजनाथ सिंह की मुलाकात वहीं कैनबरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात और उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक का भी दौरा किया।

गाजा में इस्राइली ठिकानों पर आतंकी हमला नाकाम, आईडीएफ की जवाबी कार्रवाई में कई दहशतगर्द ढेर

गाजा, एजेंसी। गाजा में आतंकवादियों ने बुधवार को इस्राइल डिफेंस फोर्स की सुरक्षा पोस्ट्स पर हमला करने का प्रयास किया। आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने कई आतंकवादियों को समाप्त कर दिया और इस घटना में आईडीएफ के किसी भी सैनिक को कोई चोट नहीं आई। आईडीएफ ने अपने एक्स अकाउंट पर बताया कि गाजा शहर क्षेत्र में कई आतंकवादियों ने आईडीएफ पोस्ट पर हमला करने का प्रयास किया। आईडीएफ सैनिकों ने वायुसेना के सहयोग से कई आतंकवादियों को समाप्त कर दिया। अतिरिक्त आतंकवादियों की खोज जारी है। इस घटना में आईडीएफ सैनिक सुरक्षित हैं। इस सप्ताहांत हो सकती है ट्रंप की मध्य पूर्व यात्रा इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इस सप्ताहांत मध्य पूर्व जा सकते हैं। उनका यह संभावित दौरा गाजा में बंदी-बदल समझौते और संघर्षविराम वार्ता के बीच हो सकता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा शांति समझौता बहुत नजदीक है और मैं शनिवार को वहां जा सकता हूं। हमारी टीम बहुत अच्छी तरह से वार्ता कर रही है। ट्रंप ने कहा मध्य पूर्व के लिए शांति एक सुंदर विचार है और हम आशा करते हैं कि यह साकार होगा। हमारी टीम और विपक्ष की टीम दोनों ही उत्कृष्ट हैं। मुझे लगता है कि यह जल्द ही होगा। इस्राइल के विदेश मंत्री ने की बैठक की आलोचना इस्राइल के विदेश मंत्री गिडियन सार ने शुक्रवार को पेरिस में होने वाली बैठक की कड़ी आलोचना की, जिसमें यूरोपीय, अरब और अन्य राजदूत गाजा के युद्धोपरांत संक्रमण और स्थायी संघर्षविराम के प्रयासों पर चर्चा करेंगे। सार ने इस पहल को अनावश्यक और हानिकारक बताया और कहा कि यह शार्म एल-शेख में चल रही वार्ता के संवेदनशील समय में इस्राइल की पीठ पीछे तैयार की गई। सार ने एक्स पर लिखा कि हम इसे राष्ट्रपति मार्क्रों का एक और प्रयास मानते हैं, जो अपने घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस्राइल का उपयोग कर रहे हैं। इस घटना के बाद गाजा में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और दोनों पक्षों द्वारा कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद इलाके में संघर्ष की आशंका बनी हुई है।

हमास-इजराइल शांति समझौते के पहले चरण पर सहमत

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। गाजा में दो साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए इजराइल और हमास ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले शांति समझौते (पीस डील) के पहले चरण पर सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। ट्रम्प ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा, जल्द ही सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और इजराइल अपनी सेना को एक तय लाइन तक वापस बुलाएगा। यह मजबूत और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा पहले चरण के तहत गाजा में इजराइल के बंधक बनाए गए लोगों को सोमवार तक रिहा किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि वे सभी सोमवार को वापस आ जाएंगे। वहीं, इस हफ्ते के आखिर तक ट्रम्प मिस्र जा सकते हैं। समझौते के 72 घंटे के अंदर बंधकों की रिहाई होगी यह समझौता मिस्र में 8 अक्टूबर को हुई इनडायरेक्ट बातचीत के बाद हुआ है। समझौते में गाजा से इजराइली सेना की वापसी और कैदियों की अदला-बदली शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, समझौते के लागू होने के 72 घंटे के भीतर लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी जीवित इजराइली बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल सरकार के प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि इजराइल को उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई जल्द शुरू होगी। बंधकों की रिहाई में मृत लोगों के शव भी शामिल हैं। कतरी मध्यस्थों ने भी समझौते की पुष्टि की है। हालांकि, इसके आगे की जानकारी बाद में घोषित करने की बात कही। कैदियों की रिहाई के बदले इजराइल गाजा से अपनी सेना पीछे हटाएगा। हमास ने ट्रम्प और गारंटर देशों से अपील की है कि वे इजराइल से समझौते का पूरी तरह पालन करवाएं। इसपर ट्रम्प ने कहा कि सभी पक्षों के साथ एक जैसा व्यवहार

किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रम्प ने कतर, मिस्र और तुर्किये को मध्यस्थता के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, यह अरब, इजराइल, अमेरिका और आसपास के सभी देशों के लिए एक महान दिन है। ट्रम्प ने 5 अक्टूबर को इजराइल की वापसी को दिखाते हुए एक मैप भी शेयर किया था। इसने उन्होंने पीली लाइन के जरिए बताया की इजराइली सेना पहले चरण में वहां तक पीछे हटेगी। बता दें कि इस संघर्षविराम के पहले चरण के तहत, हमास सात अक्तूबर 2023 के हमले के बाद बंदी बनाए गए 48 इस्राइली नागरिकों को रिहा करेगा। हालांकि, इनमें से केवल लगभग 20 लोगों के जीवित होने की उम्मीद है। इसके बदले में इस्राइल सैकड़ों फलस्तीनियों को रिहा करेगा, जिनमें महिलाएं, बच्चे और आजीवन कारावास की सजा पाए हुए कैदी शामिल होंगे। पहले के समझौतों के आधार पर, एक इस्राइली बंधक के बदले कम से कम 100 फिलिस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इतना ही नहां समझौते के तहत जब तक दोनों पक्ष पूर्ण संघर्षविराम की शर्तों को नहीं मान लेते, तब तक सभी सैन्य गतिविधियां, जैसे हवाई और तोपों से गोलाबारी रोक दी जाएंगी और सेना अपनी जगह स्थिर रहेगी। व्हाइट हाउस के अनुसार, जब सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा, तब इस्राइल 250 आजीवन कारावास पाए हुए फलस्तीनी कैदियों और हमास हमले के बाद हिरासत में लिए गए 1,700 गाजावासियों को छोड़ेगा। इसके अलावा प्रत्येक मृत इस्राइली बंधक के शव के बदले इस्राइल 15 मृत गाजावासियों के शव लौटाएगा। ट्रंप की योजना के तहत, समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटे के भीतर सभी बंधक, चाहे जीवित हों या मृत रिहा कर दिए जाएंगे। कतर के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस पहले चरण में गाजा में राहत सामग्री और जरूरी सहायता भी पहुंचाई जाएगी, जहां अब भुखमरी जैसे हालात हैं। वहीं इस संघर्ष विराम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसे ऐतिहासित बताया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि यह अरब, मुस्लिम देश, इस्राइल, आसपास के सभी देशों और अमेरिका के लिए महान दिन है। हम कतर, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थों का धन्यवाद करते हैं। गौरतलब है कि गाजा में संघर्ष की शुरुआत दो साल पहले सात अक्तूबर 2023 को हमास का इस्राइल पर हमला करने के साथ हुई थी।

वित्त विभाग ने 7,350 करोड़ की पीएलआई योजना पर उठाए सवाल

- योजना से चीन पर निर्भरता घटेगी, पर नई आयात निर्भरता पैदा होगी

नई दिल्ली ।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग (डीओई) ने भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा प्रस्तावित 7,350 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना पर सवाल उठाए हैं। यह योजना देश में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है, जिससे चीन से आयात पर निर्भरता कम की जा सके। वित्त विभाग ने चेताया कि योजना से एक निर्भरता कम जरूर होगी, लेकिन भारत को दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड के लिए अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। भारत में केवल इं डियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल) ही 500 टन ऑक्साइड की आपूर्ति कर सकती है, जबकि 5 प्लांटों के लिए सालाना 1,500 टन की जरूरत होगी। डीओई ने यह भी चिंता जताई कि भारी सब्सिडी मिलने से कंपनियों को लागत घटाने या नवाचार करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। साथ ही, अगर हर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में कमी या संकट के चलते अलग योजना

बनेगी, तो यह एक गलत उदाहरण बन सकता है। विभाग ने यह भी सवाल किया कि आरईपीएम योजना को नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत क्यों नहीं लाया गया। साथ ही यह सुझाव दिया कि सरकार को स्पष्ट दीर्घकालिक रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि दुनिया आरईपीएम के विकल्प जैसे आयरन नाइट्राइड और स्ट्रॉन्शियम-फेराइट मैग्नेट्स की ओर बढ़ रही है।

इरडा के तिमाही नतीजे 14 अक्टूबर को आएंगे, दमदार रिजल्ट की उम्मीद

कंपनी ने दूसरी तिमाही में लोन सैंक्शन और डिस्बर्समेंट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की

नई दिल्ली ।

इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (इरडा) अपने दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) के वित्तीय नतीजे 14 अक्टूबर 2025 को जारी करेगी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि इस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में तिमाही और एच1 (हाफ ईयर) के स्टैंडअलोन और कंसॉलिडेटेड नतीजों को मंजूरी दी जाएगी। इरडा ने इस तिमाही में बिजनेस के लिहाज से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कंपनी ने जुलाई से सितंबर 2025 के बीच 33,148 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन किए, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 17,860 करोड़ के मुकाबले 86 फीसदी ज्यादा है। वहीं लोन डिस्बर्समेंट 15,043 करोड़ रुपए रहा, जो साल-दर-साल आधार पर 54 फीसदी की बढ़त है। नवंबर 2023 में आईपीओ लॉन्च करने वाली इरडा का शेयर 32 रुपए पर जारी हुआ था और लिस्टिंग के दिन 50 रुपए पर खुला। तब से अब तक इसका शेयर मूल्य 149.15 रुपए तक पहुंच चुका है, जिससे निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला है। अब बाजार की नजर 14 अक्टूबर को आने वाले वित्तीय नतीजों पर है। निवेशक खासतौर पर कंपनी की आय, मुनाफा और एसेट क्वालिटी में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं।

अब अमेजन पर भी रॉयल इनफील्ड की बाइक ऑनलाइन उपलब्ध

- घर बैठे होगी डिलीवरी, पांच शहरों में शुरू हो गई सर्विस

नई दिल्ली ।

अगर आप रॉयल इनफील्ड की बाइक खरीदना चाहते हैं तो अब आपको शोरूम जाने की जरूरत नहीं होगी। अब फ्लिपकार्ट के बाद अमेजन ने भी रॉयल इनफील्ड की बाइक ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। अब अपने पसंद की बाइक को घर पर ही डिलीवर करवा सकते हैं। फिलहाल यह सुविधा देश के 5 शहरों में शुरू की गई है और आगे इसमें अन्य शहरों को भी जोड़ा जाएगा। प्रीमियम मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने बताया है कि उसके ब्रांड वाली 350 सीसी की सभी मोटरसाइकिल अब ऑनलाइन ई-कॉमर्स मंच अमेजन से खरीदी जा सकेंगी। इसमें क्लासिक 350, बुलेट 350, हंटर 350, गोअन क्लासिक 350 और नई मेट्योर 350 जैसी बाइक शामिल हैं। कंपनी के अनुसार अब ये सभी बाइक अमेजन इंडिया पर रॉयल एनफील्ड ब्रांड के बिक्री केंद्र के जरिये बेची जाएंगी। ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद अपने घर पर ही डिलीवरी ले सकते हैं। फिलहाल पांच प्रमुख शहरों अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे के ग्राहकों के लिए ही यह सेवा शुरू की गई है। इन शहरों में मोटरसाइकिल की आपूर्ति और बिक्री के बाद की सेवाएं ग्राहक के शहर में मौजूद उनके पसंदीदा रॉयल एनफील्ड डीलरशिप के जरिये की जाएगी। अमेजन से पहले फ्लिपकार्ट ने भी रॉयल इनफील्ड की बाइक को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। फ्लिपकार्ट पर 22 सितंबर यानी नवरात्र की शुरुआत से ही 350 सीसी वाली बाइकों की बिक्री शुरू की जा चुकी है। कंपनी ने बताया है कि 350 सीसी की रेंज वाली सभी बाइक उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। फ्लिपकार्ट इन बाइकों की डिलीवरी देश के 5 चुनिंदा शहरों में कर रहा है, इसमें बैंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई शामिल हैं।

एसबीआई में एमडी पद प्राइवेट बैंकरों के लिए खुला

नई दिल्ली ।

सरकार ने पहली बार देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) के पद पर प्राइवेट सेक्टर के अनुभवी बैंकरों को आवेदन करने का मौका दिया है। अब एसबीआई के चार एमडी पदों में से एक पर प्राइवेट क्षेत्र के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। यह बदलाव सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में नेतृत्व चुनने के तरीके में क्रांतिकारी माना जा रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो (एफएसआईबी) को उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रक्रिया में अब एनुअल परफारमेंस एप्रेसियल रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होगी, जो पहले शीर्ष पदों के लिए जरूरी थी। एफएसआईबी उम्मीदवारों की व्यवहारिक और कौशल क्षमता के आकलन के लिए एचआर एजेंसी की मदद भी ले सकेगा, पर चयन में एजेंसी शामिल नहीं होगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को पिछले दस साल में किसी प्रकार की सजा नहीं मिली होनी चाहिए। इस पद के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार के

पास कम से कम 21 साल का प्रोफेशनल अनुभव हो, जिसमें 15 साल बैंकिंग क्षेत्र का अनुभव अनिवार्य है। साथ ही, उम्मीदवार को किसी बैंक के बोर्ड स्तर पर दो साल या बोर्ड से नीचे टॉप लेवल पर तीन साल का अनुभव होना चाहिए।

2026 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होगी निसान टेकटॉन

नई दिल्ली ।

बहुराष्ट्रीय कंपनी निसान मोटर इंडिया ने अपनी मोस्ट-अवेटेड सी-सेगमेंट एसयूवी, टेकटॉन, का खुलासा कर दिया है। भारतीय बाजार में कंपनी इसे 2026 की दूसरी तिमाही में लॉन्च करने वाली है। टेकटॉन निसान और रेनॉल्ट की साझेदारी वाले चेन्नई प्लांट में तैयार होगी और भारत के साथ कुछ ग्लोबल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट की जाएगी। यह एसयूवी प्रीमियम और प्रैक्टिकल दोनों ही तरह की है और इसे हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हायराइडर, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन जैसी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है।

'टेकटान' नाम ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'कारीगर' या 'निर्माता।' निसान का कहना है कि यह नाम उनकी इंजीनियरिंग और डिजाइन फिलॉसफी को दर्शाता है। कंपनी इसे उन ग्राहकों के लिए पेश कर रही है जो अपने करियर, जीवनशैली और पैशन के जरिए अपनी पहचान बनाते हैं।

टेकटॉन का डिज़ाइन आकर्षक और दमदार है। इसमें फ्लैट बोनट, वी-मोशन ग्रिल, स्प्लिट हेडलैम्प्स और सी-शेप एलईडी डीआरएलएस

शामिल हैं। रग्ड बंपर, बड़े अलॉय व्हील्स और चौड़े व्हील आर्च इसे मजबूत लुक देते हैं।

टेकटॉन निसान की भारत में नई ग्रोथ स्ट्रैटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बाद कंपनी सब-4 मीटर एमपीवी और 7-सीटर एसयूवी भी पेश करेगी। साइड प्रोफाइल में हिमालय से प्रेरित डबल-सी पैटर्न है, जबकि पीछे की ओर फुल-विड्थ एलईडी टेललाइट बार, स्क्वेयर लैंप्स और रियर स्पॉइलर इसकी प्रीमियम अपील बढ़ाते हैं। पावरट्रेन के मामले में यह एसयूवी सीएमएफ-बी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, और टॉप वैरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव भी हो सकता है।

रुपया बढ़त के साथ बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को भारतीय रुपया 13 पैसे की बढ़त के साथ ही 88.66 पर बंद हुआ। सबह अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 88.80 पर कमजोर खुला, लेकिन जल्द ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.78 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से एक पैसे की बढ़त है। गुरुवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 88.79 पर बंद हुआ था। कारोबारियों ने कहा कि मजबूत अमेरिकी डॉलर और आयातकों की मांग के कारण रुपये पर दबाव पड़ा। हालांकि, घरेलू बाजारों में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में कमी ने गिरावट पर अंकुश लगाया। छह मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को बताने वाला डॉलर सूचकांक 0.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.32 पर रहा।

असम में चाय उद्योग में सभी उत्पादकों की जगह बनी रहनी चाहिए: रवि कोटा

कोलकाता । असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने कहा है कि राज्य के चाय उद्योग में मौजूद दोहरी संरचना, जिसमें बड़े संगठित उत्पादक और छोटे चाय उत्पादक (एसटीजी) शामिल हैं, भविष्य में भी बनी रहनी चाहिए। उन्होंने इस संरचना को आवश्यक बताते हुए कहा कि दोनों को एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना सह-अस्तित्व बनाए रखना होगा। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जो देश की सालाना चाय उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा देता है। बड़े संगठित उत्पादकों को बागान अधिनियम के तहत कई कल्याणकारी दायित्व निभाने होते हैं, जबकि छोटे उत्पादक इन दायित्वों से मुक्त हैं। एसटीजी का योगदान भारत की कुल चाय उत्पादन में 50 फीसदी से अधिक है। कोटा ने चाय के लिए न्यूनतम स्थायी मूल्य (एमएसपी) लागू करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाना चाहिए जो किसानों के लिए न्यायसंगत हो। साथ ही चाय के आयात में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उत्पाद के मूल स्रोत की जानकारी उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए।

जुबिलेंट हॉलिस्टरस्टियर करेगी अमेरिका में 300 मिलियन डॉलर का निवेश

- स्टेराइल इंजेक्टेबल्स की उत्पादन क्षमता होगी दोगुनी

नई दिल्ली । जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड की अमेरिकी शाखा जुबिलेंट हॉलिस्टरस्टियर एलएलसी अमेरिका में अपनी स्टेराइल इंजेक्टेबल दवाओं की उत्पादन क्षमता को दोगुना करने के लिए 300 मिलियन डॉलर (लगभग 2,500 करोड़) का निवेश करेगी। यह निवेश वित्त वर्ष 2027-28 तक पूरा होने की योजना है। कंपनी ने यह विस्तार वाशिंगटन के स्पोकेन में स्थित अपने विनिर्माण संयंत्र में किया है, जहां तीसरी उत्पादन श्रृंखला की स्थापना 132 मिलियन डॉलर की लागत से की गई है। कंपनी के एक व रिष्ठ अ धिकारी ने बताया कि यह वेश कंपनी की उत्पादन क्षमता को मौजूदा 5 करोड़ शीशियों से बढ़ाकर 10 करोड़ शीशियों प्रति वर्ष कर देगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फार्मा उत्पादों पर लगाए गए भारी शुल्कों के चलते लिया गया है, ताकि अमेरिकी बाजार में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिल सके और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा सके।

JUBILANT PHARMOVA

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुम्बई ।

घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी रहने से आया है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 328.72 अंक की बढ़त के साथ 82,500.82 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 103.55 अंक बढ़कर 25,285.35 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

आज निफ्टी पर 3,174 शेयरों में से 1,905 शेयर तेजी के साथ बंद हुए। वहीं 1,177 शेयरों में गिरावट दर्ज की गयी। इसके अलावा 92 शेयरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया।

आज सिप्ला , एसबीआई , मारुति सुजुकी , डॉ. रेड्डीज़ लैब्स व भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर बढ़त पर बंद हुए जबकि टा स्टील, टीसीएस व एचडीएफसी लाइफ का शेयरगिरावट के साथ 747.30 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील और टेक महिंद्रा के शेयर में भी गिरावट रही। इससे पहले आज सुबह सेंसेक्स 50 से ज्यादा अंक की गिरावट लेकर 82,075.45 पर खुला। खुलने के बाद इंडेक्स में गिरावट बढ़ गई और यह 82,072 तक फिसल गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी गिरावट के साथ 25,167.65 पर खुला। । एशिया के बाजारों में वॉल स्ट्रीट की तरह ही गिरावट देखी गई। चीन का सीएसआई 300 इंडेक्स 1.08 प्रतिशत, हांगकांग का हैंगसेंग 0.85 फीसदी और जापान का निक्केई 0.63 फीसदी नीचे आया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.81 फीसदी ऊपर रहा। अमेरिकी शेयर बाजार अपने हालिया रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे गिर गए। एसएंडपी 500 में 0.28 फीसदी की गिरावट आई। नैस्डैक में 0.08 फीसदी की गिरावट आई और डॉव जोन्स 0.52 फीसदी गिरकर बंद हुआ।

एयर इंडिया की नई उड़ान सेवा दिल्ली से लंदन 26 अक्टूबर से

नई दिल्ली । एयर इंडिया ने आगामी शीतकालीन मौसम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और लंदन (हीथ्रो) के बीच अपनी चौथी दैनिक उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। यह नई सेवा 26 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके साथ ही लंदन रूट पर एयर इंडिया की कुल साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 24 से बढ़कर 28 हो जाएगी। कंपनी के अनुसार, इस अतिरिक्त उड़ान से यात्रियों के लिए प्रति सप्ताह 1,196 सीटें और उपलब्ध हो जाएंगी। सर्दियों के व्यस्त मौसम को देखते हुए यह कदम यात्रियों को अधिक विकल्प और लचीलापन प्रदान करेगा। नई उड़ान सेवा से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार, पर्यटन और पारिवारिक यात्रा को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एयर इंडिया का यह विस्तार अंतरराष्ट्रीय संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम माना जा रहा है।

इक्सिगो 1,296 करोड़ में प्रोसस को 10.1 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा

नई दिल्ली । यात्रा बुकिंग मंच इक्सिगो ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसे वैश्विक प्रौद्योगिकी निवेशक प्रोसस से 1,295.56 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा। यह निवेश तरजीही इक्विटी निर्गम के माध्यम से किया जाएगा। प्रोसस की सहायक कंपनी एमआईएच इंवेस्टमेंट वन बी.वी. को 280 रुपए प्रति शेयर की दर से 4.62 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जो कंपनी की कुल चुकता पूंजी का 10.1 फीसदी है। इक्सिगो ने बताया कि यह पूंजी कंपनी की विस्तार योजनाओं, कार्यशील पूंजी जरूरतों और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में उपयोग की जाएगी। इस निवेश के साथ, इक्सिगो को न केवल वित्तीय मजबूती मिलेगी, बल्कि एक अनुभवी वैश्विक निवेशक का साथ भी मिलेगा, जो इसके भविष्य के विकास में सहायक हो सकता है।

आईपीओ के ज़रिए भारत ने जुटाए 14.2 अरब, दुनिया में चौथे स्थान पर

- 74 कंपनियों ने जुटाए 85,241 करोड़, छोटे आईपीओ ने दिए 40 फीसदी तक रिटर्न

मुंबई ।

घरेलू शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत ने वर्ष 2025 में आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) के ज़रिए पूंजी जुटाने के मामले में दुनिया में चौथा स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियों ने इस वर्ष कुल 14.2 अरब डॉलर (85,241.08 करोड़) जुटाए, जो पिछले पांच वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी राशि है। भारत से आगे अमेरिका (52.9 अरब डॉलर), हांगकांग (23.4 अरब डॉलर) और चीन (16.2 अरब डॉलर) रहे।

इस वर्ष भारत में कुल 74 कंपनियों ने आईपीओ लाए, हालांकि इसमें बीवर्क इंडिया, टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया जैसे तीन बड़े आईपीओ शामिल नहीं हैं, जो लगभग 30,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में हैं। जनवरी 2024 से अब तक 21 महीनों में 161 कंपनियों के आईपीओ सूचीबद्ध हुए हैं, जिनमें निवेशकों को औसतन 22 फीसदी रिटर्न मिला, जो निफ्टी जैसे प्रमुख सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन है। इनमें से 61 फीसदी आईपीओ ने छह महीने में निफ्टी से अधिक रिटर्न दिया। विश्लेषण में यह भी सामने आया कि छोटे आकार के आईपीओ अधिक लाभदायक रहे हैं। 2 डॉलर मिलियन से कम वाले आईपीओ ने 40 फीसदी तक का रिटर्न दिया, जबकि 1 अरब डॉलर से अधिक के बड़े

आईपीओ का औसत रिटर्न केवल 9 फीसदी रहा। गौरतलब है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 2025 में सेकेंडरी मार्केट से जहां 18 अरब डॉलर निकाले, वहीं प्राथमिक बाजार में 5 अरब डॉलर का निवेश किया। यह भारत के आईपीओ बाजार में उनके भरोसे को दर्शाता है।

भारत में 47 फीसदी आबादी अब भी ऑफलाइन

- महिलाओं की डिजिटल भागीदारी 33 फीसदी कम

नई दिल्ली। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (जीएसएमए) की ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारत की लगभग 47 प्रतिशत आबादी अब भी इंटरनेट से जुड़ी नहीं है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में जीएसएमए एशिया एक अे धिकारी ने यह जानकारी साझा की। गोर्मन के अनुसार, डिजिटल पहुंच में सबसे बड़ी बाधा मोबाइल डिवाइस की ऊंची कीमतें और तकनीकी ज्ञान की कमी है। इसके अलावा, मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करने में महिलाएं पुरुषों से 33 प्रतिशत पीछे हैं। यह बढ़ता डिजिटल लैंगिक अंतर देश के समावेशी विकास के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। जीएसएमए की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2013 के 108 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 370 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, और 2030 तक इसके 1,000 अरब डॉलर को पार करने की संभावना है। लेकिन यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर डिजिटल पहुंच और नवाचार में असमानता दूर नहीं की गई, तो 2047 तक भारत के डिजिटल संप्रभुता लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट ने यह भी उजागर किया कि भारत डिजिटल बुनियादी ढांचे और मोबाइल अपनाने में अग्रणी है, पर अनुसंधान एवं विकास, निजी क्षेत्र की भागीदारी और कुशल तकनीकी पेशेवरों की उपलब्धता के मामले में अभी भी पिछड़ रहा है।

नीरू बाजवा ने की नई फिल्म की घोषणा

बॉलीवुड फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में अपनी अदाकारी से सभी को अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस नीरू बाजवा ने अपनी नई पंजाबी फिल्म जवाक की घोषणा सोशल मीडिया हैंडल पर की है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठाया है। नीरू बाजवा ने 5 अक्तूबर 2025 को अपनी आगामी फिल्म जवाक की घोषणा इंस्टाग्राम पोस्ट पर की है। इस पोस्ट के साथ नीरू ने कैप्शन में लिखा, और अधिक पढ़ें...अपने आंद्रे जवाक नू हमेशा जिओंदा राखो, जे वड्डे बन ना ता। सिनेमाघरों में 17 अप्रैल 2026। जवाक का निर्देशन जतिंद्र महुअर कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण संतोष सुभाष कर रहे हैं। जबकि फिल्म की स्क्रिप्ट जगदीप वारिंग ने लिखी है। यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

नीरू बाजवा का करियर

हाल ही में नीरू बाजवा अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में नजर आई थीं। नीरू ने अपने करियर की शुरुआत देव आनंद की हिंदी फिल्म मैं सोलह बरस की (1998) से की थी, जिसके बाद उन्होंने कई हिंदी टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया. उन्होंने पंजाबी सिनेमा में अपनी खास जगह बनाई और जट्ट एंड जूलियट, सरदार जी, लौंग लाची, शादा, काली जोत्ता जैसी कई हिट फिल्में दीं। अभिनय के अलावा नीरू निर्देशन और प्रोडक्शन में भी हाथ आजमा चुकी हैं। उन्हें तीन बार पीटीसी पंजाबी फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हॉलीवुड की फिल्म इट लिव्स इनसाइड से शुरुआत की है।

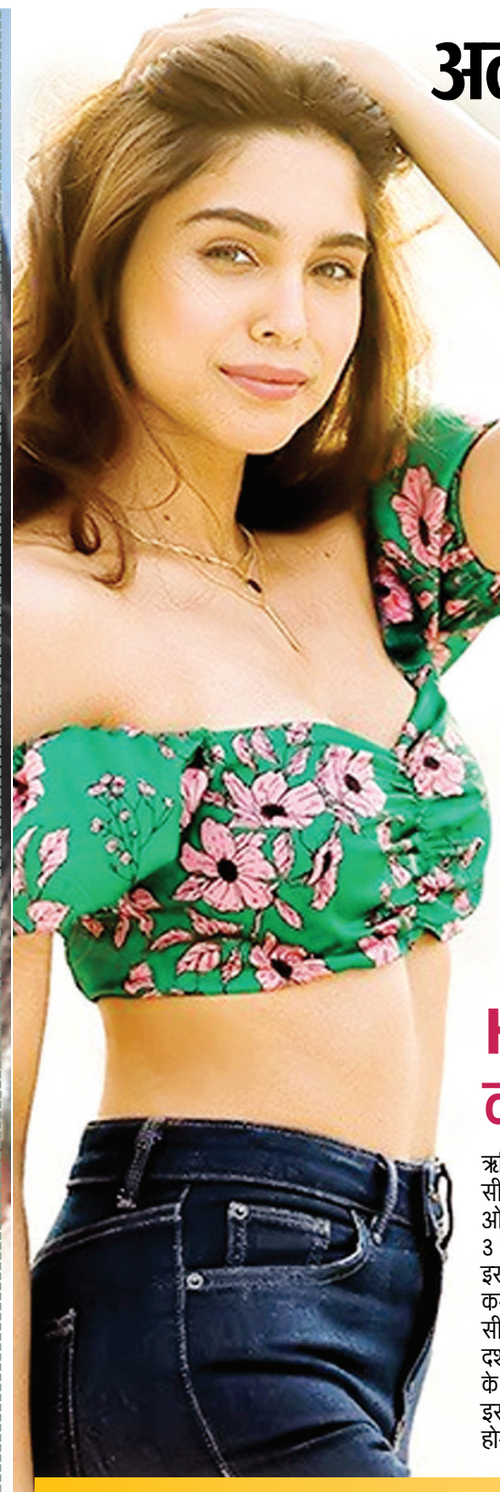

अली अब्बास जफर की फिल्म में दिखेगी अहान पांडे और शरवरी वाघ की जोड़ी

'सैयारा' फेम अहान पांडे और शरवरी वाघ की जोड़ी बड़े पर्दे पर पहली बार साथ दिखाई देगी। यह जोड़ी अली अब्बास जफर की नई फिल्म में साथ दिखाई देने वाली है, इस बात की पुष्टि हो गई है। फिलहाल फिल्म का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन पता चला है कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस शरवरी वाघ ने इसके अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने इस खबर की पुष्टि करते हुए आईएएनएस से कहा, सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है और अहान पांडे आज हमारे देश के सबसे बड़े जेन जी अभिनेता हैं। शरवरी 100 करोड़ रुपये की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुंज्या का भी हिस्सा थीं। आपके पास दो शानदार कलाकार हैं जिन्होंने साबित

कर दिया है कि सिर्फ उम्दा अभिनय ही लोगों को सिनेमाघरों तक खींच सकता है। उन्होंने आगे कहा, दशकों बाद आपके पास बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परिणाम देने वाले नवोदित और युवा कलाकार हैं। यह अली अब्बास जफर जैसे बड़े फिल्म निर्माताओं को एक ऐसी युवा फिल्म बनाने के लिए उत्साहित करता है, जो रोमांटिक होने के साथ ही एक एक्शन फिल्म भी है। सूत्र ने आगे कहा कि इन दोनों युवा कलाकारों को डायरेक्ट करने के लिए अली अब्बास जफर भी उत्साहित हैं। फिल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है। इसे आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे ब्रदर की दुल्हन, गुंडे, सुल्तान और टाइगर जिंदा है के बाद अली जफर और आदित्य चोपड़ा की यह पांचवीं फिल्म है। एक अन्य शख्स ने बताया कि मेकर्स को सैयारा की सफलता के बाद अहान पांडे पर भरोसा बढ़ा है। उनका मानना है कि अहान के अंदर जेन जी को सिनेमाघरों में लाने की ताकत है, इसलिए वे भी इसे भुनाना चाहते हैं। कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थीं कि दोनों साथ काम कर सकते हैं, अब यह बात पुख्ता हो गई है। वैसे पर्दे पर पहली बार शरवरी वाघ और अहान पांडे की जोड़ी साथ दिखाई देगी। इस बारे में जानने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग इस फिल्म के लिए अभी से ही उत्साहित हैं।

HRX फिल्म्स के बैनर तले ऋतिक करेंगे पहली सीरीज का निर्माण

ऋतिक अमेजन प्राइम वीडियो के लिए एक सीरीज बनाने वाले हैं। ऋतिक का एक बड़ा ओटीटी प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस पर वो पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। अजितपाल सिंह इस सोशल थ्रिलर सीरीज के निर्देशन की कमान संभाल रहे हैं, जो इससे पहले वेब सीरीज टब्बर के जरिए एक खूबसूरत कहानी दर्शकों के बीच पेश कर चुके हैं। इस सीरीज के प्री-प्रोडक्शन का काम चल रहा है। इसकी शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू होगी। सबा के साथ अलाया एफ भी इसमें अहम भूमिका में हैं, वहीं आशीष विद्यार्थी विलन बने हैं। ऋतिक का पूरा ध्यान फिलहाल प्रोडक्शन पर है, ताकि जो विजन इसके लिए उन्होंने सोचा था, वो हासिल किया जा सके। ये बतौर निर्माता ऋतिक की पहली सीरीज है। इसके बाद ऋतिक कृष 4 पर काम करेंगे, जिसके निर्देशन की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। पिछली बार उन्हें वेब सीरीज क्राइम बीट में छोटी सी भूमिका में देखा गया था।

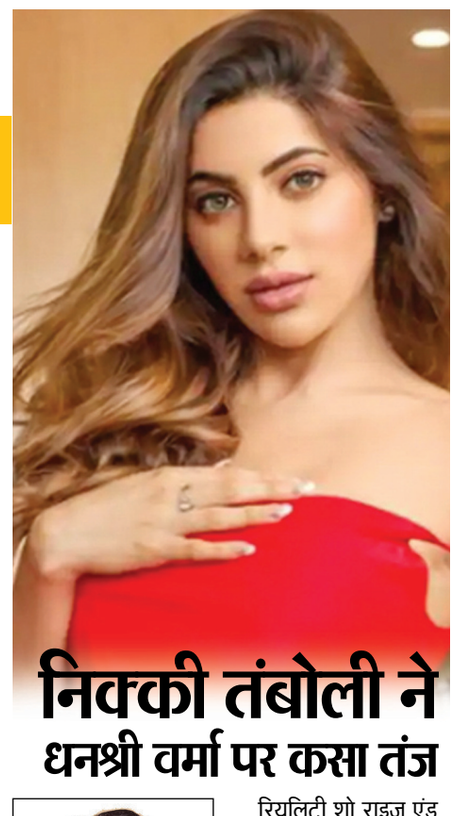

निक्की तंबोली ने धनश्री वर्मा पर कसा तंज

रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रहे अरबाज पटेल की गर्लफ्रेंड निक्की तंबोली ने हाल ही में शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने धनश्री वर्मा को एक्सपोज किया है। दरअसल, निक्की ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसमें धनश्री कहती है निक्की ने जानबूझकर मेरे सामने बोला कि लोग वीडी में क्या बात करते हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। बुलाओ उसे, बुलाओ सभी वीडी वालों को। मैंने एक बार भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। निक्की ने इस क्लिप के साथ कैप्शन लिखा, वफादारी की अदाकारी मत करो हमारे सामने, हम शक्ल से नस्ल पहचानने का हुनर रखते हैं। बता दें, निक्की हाल ही में शो में आई थीं। इस दौरान उन्होंने अरबाज से कहा था गेम में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है धनश्री से। वह इस सीजन में राइज एंड फॉल की सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली प्रतियोगी हैं।

अक्षय ओबेरॉय ने यश के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की

अभिनेता अक्षय ओबेरॉय हाल ही में फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आए हैं। यह फिल्म इन दिनों सिनेमाघरों में बनी हुई है। अब अक्षय ने फिल्म 'टॉक्सिक' में साउथ सुपरस्टार यश के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की।

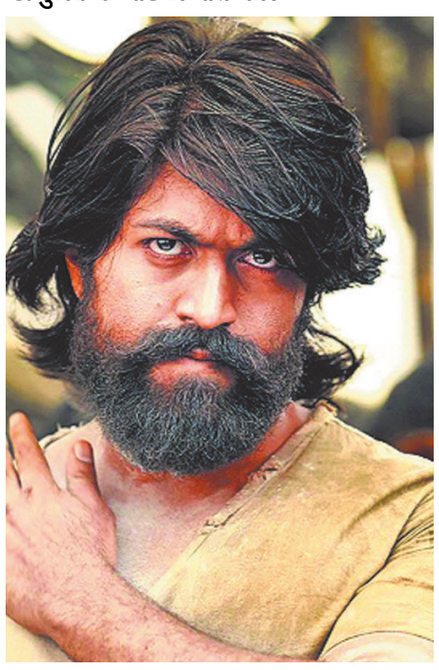

अक्षय ने बताया कि टॉक्सिक की सबसे बड़ी उपलब्धि यश के साथ काम करने का मौका था। पूरी दुनिया यश की प्रशंसक है। उनके साथ काम करके, मैंने इतना कुछ सीखा कि मुझे एहसास हुआ कि मुझमें क्या कमी थी। मैं यहां यह कह रहा हूं कि काश इंडस्ट्री मुझे ज्यादा नोटिस करती और आप ये सवाल पूछ रहे हैं मैं इससे सहमत हूं। लेकिन वह वन-मैन इंडस्ट्री की तरह हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। उन्हें अपनी प्रतिभा साबित करने या ऑफर देने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। उन्हें अवसरों की जरूरत नहीं है, वह खुद उन्हें बनाते हैं। यह बहुत प्रेरणादायक है। वह एक-व्यक्ति, चलता-फिरता, बोलता इंडस्ट्री है। मैं बस यही सोचता था कि अगर मैं उनके इस कैरेक्टर और ऊर्जा को पकड़ सकता हूं, तो मुझे भी कोई नहीं रोक सकता। 'टॉक्सिक' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फैंस गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित 'टॉक्सिक' अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। इसे यश की आगामी मच अवेटेड फिल्मों में गिना जा रहा है। फिल्म की कहानी को लेकर अभी तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
फिल्म को पहले इसी साल रिलीज होना था, लेकिन अब इसे अगले साल 2026 में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी। 'टॉक्सिक' के अलावा यश नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर भी चर्चाओं में हैं।

साउथ में और भी काम करना चाहते हैं अक्षय

टॉक्सिक को लेकर अक्षय ने कहा कि फैंस ढेर सारे सरप्राइज की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस फिल्म के बारे में जितना कम कहूं, उतना ही अच्छा है। फिल्म में ढेर सारे सरप्राइज हैं। मुझे अपने किरदार में बहुत मजा आया और मुझे एक्शन करना बहुत पसंद है। आगे साउथ में और भी काम करने पर एक्टर ने कहा कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। मैं मलयालम, तेलुगु या तमिल फिल्म में काम करना पसंद करूंगा। मुझे साउथ में काम करने का अनुभव बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे वहां से और भी काम मिलेगा। नई भाषा में काम करने की चुनौती के बारे में अक्षय ने कहा कि मुझे भाषाओं और लहजों में रुचि है और मुझे उनसे आनंद मिलता है। बेशक यह एक चुनौती है, लेकिन मुझे इसमें बहुत मजा आता है। भाषाएं और लहजे सीखना मेरे लिए स्वाभाविक है। इसलिए मुझे काम में मजा आया।

एक एक्टर और निर्देशक के रूप में कांतारा मेरे लिए एग्जॉस्ट करने वाली फिल्म रही

क्लैपर बॉय से एक्टर-डायरेक्टर बनने के सफर में ऋषभ शेट्टी के करियर में कड़े संघर्ष के कई दौर आए, मगर कलाकार बनने का उनका जज्बा कभी भी धूमिल नहीं हुआ। सहायक निर्देशक और एक-दो सीन वाली भूमिकाएं करने वाले ऋषभ ने गुजारे के लिए छोटे-बड़े सभी काम किए और आखिरकार उनकी किस्मत का सितारा चमका कांतारा की सुपर सक्सेज से। इन दिनों वे चर्चा में हैं कांतारा चैप्टर 1 से।

एक अदाकार के रूप में आपकी यात्रा के बारे में बात करूं, तो उसमें भी कई उतार-चढ़ाव और संघर्ष रहा?

हर किसी को अपने हिस्से का संघर्ष तो करना ही पड़ता है। खास तौर पर मैं अगर आर्ट फॉर्म की बात करूं, तो आप उसे नहीं चुनते बल्कि वो आपको चुनता है। आपको यहां तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ता है। मैं अपने संघर्ष को एक प्रोसेस मानता हूं। ये सच है कि मैंने छोटे-बड़े सभी काम किए हैं। मैं पानी की बोतलें बेचा करता था। मैंने रियल एस्टेट और होटल में भी काम किया। इंडस्ट्री में मैंने क्लैपर बॉय के रूप में शुरुआत की। कई छोटे-छोटे रोल्स किए, मगर मैंने कभी किसी काम को कमतर नहीं समझा। अपनी पहली कमाई आज भी याद है मुझे। पानी की बोतल बेच कर मैंने 25 रुपए कमाए थे। मैं एक बड़ी मैडम के घर पानी पहुंचाने गया था और उस काम के मुझे 25 रुपए मिले थे। उस वक्त पच्चीस रुपए भी बहुत बड़ी रकम लगी थी मुझे।

आप एक ऐसे कलाकार हैं, जो परिवार को साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं।

बिलकुल, क्योंकि परिवार नहीं होगा, तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। मेरी पत्नी प्रगति कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। इस पार्ट वन और टू की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग उन्होंने ही की है। पार्ट वन रहा हो या टू वे पूरी तरह से मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ रहीं। खतरनाक एक्शन सीन्स के दौरान वे लगातार भगवान से प्रार्थना करती थीं। उन्हें पूरी यूनिट की चिंता रहती थी। शूटिंग के दौरान मैं महीनों तक घर नहीं जा पाता था, क्योंकि हमें लगातार शूटिंग करनी होती थी, ऐसे समय में मैं लोकेशन के आस-पास की जगहों या होटल्स में ठहरता था ताकि अगले दिन समय पर शूटिंग में पहुंच सकूं। एक एक्टर और निर्देशक के रूप में कांतारा मेरे लिए एक एग्जॉस्ट करने वाली फिल्म रही है, ऐसे में भावनात्मक रूप से उन्होंने ही मुझे संभाला। शूटिंग दौरान वे घर में बच्चों की देखरेख भी कर रही थीं और मुझसे मिलने शूटिंग पर भी आया करती थीं।

आज दर्शक हर भाषा में कॉन्टेंट देख रहा है, मगर भाषा के नाम पर जो विवाद पैदा किए जाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?

हमारी डायवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे समझाना होगा। तभी तो हमारे करेंसी नोट पर कोई एक भाषा नहीं होती। हमारे नोट पर जितनी भाषाएं हैं, असल में हमारे पास उससे भी कहीं अधिक लैंग्वेज हैं। यही भारत की पहचान है। मेरा मानना है कि भाषा पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हम सभी को एक-दूसरे की भाषाओं को सम्मान देना चाहिए। हमारी मातृभाषा हमारे चरित्र की परिचायक है। हम जब सामने वाले की भाषा को इज्जत देंगे, तभी हमारी भाषा को रिस्पेक्ट मिलेगी।

अपनी पहली फिल्म कांतारा से पैन इंडिया स्टार का दर्जा हासिल करना कैसा लगता है?

सच कहूं, तो मैं इन बातों को नहीं समझता। मुझे तो यही सब जिम्मेदारी लगती है। मुझे लगता है कि मुझे यदि देश भर के लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। मुझे और अधिक कोशिश करनी होगी कि मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूं। सफलता और तारीफ हासिल करने के बाद मुझे लगता है कि मेहनत डबल हो जाती है।

फिल्म में एक्टर-डायरेक्टर की दोहरी जिम्मेदारी का संतुलन कैसे स्थापित किया

इसका श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। चाहे वो मेरे राइटर्स की टीम हो , प्रोड्यूसर हों या कैमरामैन, मैं अगर कोई एक आइडिया पिच करता हूं, तो हर कोई मेरा साथ देने को तैयार हो जाता है। हम साथ मिलकर आईडिया एक्स्प्लोर कर लेते हैं। अब जैसे इस फिल्म की मूल कहानी हमारे देव कोला और लोक कथाओं से प्रेरित थी। जब इस कहानी का विचार आया तो सभी को भा गया। मुझे लगता है, किसी भी फिल्म की सफलता का क्रेडिट टीमवर्क को जाता है।